साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 18 01 - 07 मई 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

ईदुल फ़ित्र के अहकाम व मसायल
पृष्ठ - 6

आलमे इस्लाम में ईदुल फित्र मनाने का तरीक़े
पृष्ठ - 7

जी-23 बनाम राहुल गांधी
कांग्रेस में अंदरूनी तकरार
आख़िर सच्चाई क्या है?

कांग्रेस दिन-प्रतिदिन अपनी गरिमा खोती जा रही है जिसके कारण इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के चाहने वाले हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हैं।

ये कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस के भीतर ताक़त पाने की लड़ाई है। एक ओर जी-23 है तो दूसरी ओर गांधी परिवार के करीबी वो नेता जिनके हाथ कांग्रेस की कुंजी थमा दी गई है। बिना गांधी परिवार दोनों का अस्तित्व नहीं हैं तो कांग्रेस का अस्तित्व भी गांधी परिवार के बग़ैर नहीं है। यानि जैसे ही राहुल गांधी का नाम आएगा वैसे ही हर नेता ख़ामोश हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर कोई दूसरा अगर कांग्रेस को हांकेगा तो ये पुराने कांग्रेसी कैसे बर्दाश्त करेंगे। पर राहुल गांधी अब उस कांग्रेस को बदलना चाहते हैं जिसने सिर्फ सत्ता देखी। शायद इसलिए जी-23 की पूरी कतार ही कांग्रेस की सत्ता की प्रतीक है।

कोई सीएम रहा है तो कोई कैबिनेट मंत्री और किसी ने सत्ता की मलाई किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठकर खाई है। अब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है उसे संघर्ष की ज़रूरत है। तो संघर्ष करने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े हों या सत्ता के दौर में सत्ता के ज़रिये पहचाने जाने वाले कांग्रेसियों के साथ। 24, अकबर रोड के भीतर और बाहर कांग्रेस के संकट को लेकर ये तमाम सवाल जिस साफगोई के साथ हर कोई उठाने से चूकता नहीं, वहीं रास्ता पूछने पर एक ख़ामोशी रेंगे जाती है। किसी-किसी की अंगुली 24 अकबर रोड के भीतर से 10 जनपथ की ओर जाते उस कांग्रेसी रास्ते पर ज़रूर उठ जाती है जहां से अक्सर गांधी परिवार 24 अकबर रोड में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचता है।

दरअसल कांग्रेस के संकट की असल कहानी भी यहीं से शुरू होती हैं, जिसमें तीन प्रश्न सबसे बड़े हैं। पहला, जी-23 किसी भी हालत में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानि सीडब्ल्यूसी पर कब्ज़ा करना चाहता है। यानि उसे गांधी परिवार से कोई गिला शिकवा नहीं लेकिन भविष्य में सीडब्ल्यूसी के भीतर की पटकथा अपने हिसाब से लिख सके, इस ताक़त को वो गंवाना नहीं चाहते हैं। दूसरा, सत्ताधारी रहे कांग्रेसी संघर्ष के रास्ते पर क्यों नहीं निकलते जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद धूल फांकते हुए राजनीति कर रहे हैं। यानि जी-23 का संघर्ष पार्टी को खड़ा करने से ज़्यादा पार्टी के भीतर ताक़त पाने की लड़ाई है।

तीसरा, राहुल गांधी अपने नेतृत्व में जिस कांग्रेस की कल्पना किए हुए है वो पारंपरिक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस नहीं है। बल्कि संघर्ष करने वालों के साथ खड़े होकर युवा स्फूर्त कांग्रेस को बनाने की है। यानि जी-23 जिस कांग्रेस का राग अलाप रही है राहुल गांधी उसमें न तो मोदी से टकराने की ताक़त देखते हैं न ही संघ परिवार को चुनौती देने का माद्दा। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई नई कांग्रेस की सोच राहुल गांधी के दिमाग़ में पनप रही है या फिर राहुल गांधी की नई कांग्रेस की सोच दिवास्वप्न की तरह है, जिस पर कपिल सिब्बल 'घर की कांग्रेस और सबकी कांग्रेस' का तंज़ कसने से नहीं कतराते। दरअसल संसद हो या सड़क, कोई रैली हो या मीडिया के सामने प्रश्न-उत्तर की स्थिति हर जगह जिन बातों को राहुल गांधी सीधे कर रहे हैं वा पारंपरिक सत्ताधारी कांग्रेस कही कते ही नहीं हैं। कहते भी हैं तो कुछ इस अंदाज़ में जैसे दिन के उजाले में कांग्रेस का हित साधते नज़र आए और रात के अंधेरे में सत्ता की चौखट पर नतमस्तक नज़र आएं जिससे उनकी कोई फाइल न खुल जाए। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेसियों को जो पाठ पढ़ाया वह नई कांग्रेस को काफी हद तक परिभाषित करता है। जिसमें सत्ता से समझौता करने वाले या संघ को निशाने पर न ले पाने वाले की कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता पांच मुद्दों को उठाता है - प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर लेना, संघ की विचारधारा के ख़िलाफ़ कांग्रेसी की धारा को खड़ा करने की मशक्कत करना, कारपोरेट पूंजी या देश की पूंजी कॉपोरेट के हाथों सौंपने का विरोध करना, युवाओं को देश की

बाक़ी पेज 11 पर

मज़हबी त्योहारों के नाम पर नफ़रत का यह तूफान क्यों?

देश में छह से ज़्यादा प्रदेशों में क्या नफ़रत भरी अभिव्यक्तियों की श्रृंखला चल रही है? दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से बंगाल तक करीब पन्द्रह बीस घटनाएं ऐसी हैं, जिनकी गंभीरता को समझना राष्ट्रहित में ज़रूरी है। अगर चल रहे नफ़रती तीरों के तरकश देखें, तो कोई भी पक्ष निर्दोष नज़र नहीं आता है। हर ओर से हमले तेज़ हो गए हैं। कटु जवाब देने के साथ ही तत्काल हिसाब बराबर कर देने की जल्दी भी बहुत है। धर्म या नफ़रत के कथित जानकार और ज़िम्मेदार लोग भी नफ़रती बयानबाज़ी से बाज़ नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ लोग इतने भटक गए हैं कि मुंह खोलते ही ज़हर उगलने लगते हैं? क्या कथित धर्मक्षेत्र के लोगों की भाषा में प्रेम व मानवीयता का अभाव नहीं हो गया है? क्या प्रेम के बिना भक्ति या वैश्विक सद्भाव और सबका कल्याणा संभव है? ख़तरे को ऐसे बढ़ाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, मानो ख़तरा बस दरवाज़े के बाहर खड़ा हो? हर पक्ष खुद को निर्दोष और पीड़ित मान रहा है। सकारात्मकता की चर्चा बंद करके।

नकारात्मकता में बराबरी की खोज हो रही है। कानून के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों का भी सम्मान करने वाले लोग कौन हैं? हम कैसा समाज बना रहे हैं? ऐसे प्रश्नों का हुजूम उमड़ पड़ा है और दस से ज़्यादा राज्यों में ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। कितनी घटनाओं और कितने भटके हुए लोगों का यहां ज़िक्र करें? सत्संग में बैठने वालों के मुंह से बदज़बानी की सूचि लंबी है जबकि सभी ने बचपन में यह पढ़ा है - *रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ा चटकाय, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परि जाय*। लेकिन अब शायद बहुत से लोग इस दोहे या उसके भाव को भूलने लगे हैं। याद रहे, कट्टरता को भूलकर ही यह देश आगे बढ़ा था और आज विकास की डगर में आगे निकल आया है और अनेक देशों के लिए मिसाल बन गया है। आज लोगों को अनगिनत नकारात्मक टिप्पणियां और उदाहरण याद हैं, पर सकारात्मक टिप्पणियां और सद्भाव के अनगिन उदाहरणों को नज़रअंदाज़ करने वाले लोग क्या चाहते हैं?

सबसे बड़ा प्रश्न है कि कानून या संविधान क्या चाहता है? इन दंगों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। केन्द्र में सत्तारुढ़ पार्टी अक्सर यह दावा करती रही है कि उसके राज में दंगें नहीं होते? क्या उसके शासन पर कोई साज़िशन दंगे के दाग़ लगाना चाहता है? सुरक्षा एजेंसियों को अमन बनाए रखने के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि नफ़रती बयार को काबू में करने के लिए हरेक कदम कानून सम्मत उठाने पड़ेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग किसी को नहीं करने देना चाहिए। ऐसे दंगे आर्थिक तरक्क़ी को सीधे प्रभावित करते हैं। युवाओं को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करना ज़रूरी है। ख़ाली पड़े सरकारी पदों को तत्काल प्रभाव से भरने की ज़रूरत है। सेना में भर्ती भी ज़रूरी है, ताकि युवा शक्ति का देश की मज़बूती में वाजिब उपयोग हो सके। किसने कितनी नौकरी का वादा किया था, यह बात भूल जाइए, लेकिन ग़ौर कीजिए एक अनुमान के अनुसार केन्द्र और सरकारें अगर चाहें, तो करीब 60 लाख युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। जिस विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसके लिए अमन चैन बुनियादी ज़रूरत है। जो भी देश दुनिया में अपनी मेहनत से विकसित हुए हैं, उनके शासन प्रशासन से हमें सीखना चाहिए। बेशक, आज विकास के ज़रूरी तत्वों संसाधनों को जोड़ रखने के लिए सद्भाव भरे वचनों- वक्तव्यों की ज़रूरत है। ❑❑

पाकिस्तान

बाजवा के शांति संदेश की वजह

सुधींद्र कुलकर्णी

पाकिस्तान ने हाल ही में एक गंभीर सांविधानिक संकट का सामना किया, जिसे वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। नेशनल असेम्बली में बहुमत गंवाने के बावजूद सत्ता में बने रहने की कोशिश का ख़ामियाज़ा भुगतने के बाद इमरान ख़ान ने इस्तीफा दे दिया है। शाहबाज़ शरीफ़ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के नज़रिये से इस उथल-पुथल के दौरान दो सकारात्मक बातें हुईं। पहली तो यही कि अमेरिका के नेतृत्व में अपनी सरकार गिराने की विदेश साज़िश का आरोप लगाने वाले इमरान ख़ान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर प्रशंसा की। और इससे भी महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ताक़तवर सैन्य प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने एक बार फिर भारत के पास शांति का संदेश भेजा है, जिसे मोदी सरकार को ख़ारिज नहीं करना चाहिए

विगत 02 अप्रैल को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा, 'पाकिस्तान कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का इस्तेमाल करने में विश्वास रखता है और अगर भारत ऐसा करने के लिए सहमत होता है, तो वह इस मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता साझा क्षेत्रीय समृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। हमारे दरवाज़े सभी पड़ोसियों के लिए खुले हैं। अपनी बात को घरेलू स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में दुनिया का एक तिहाई हिस्सा कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार के संघर्ष में शामिल है, ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्षेत्र से आग की इन लपटों को दूर रखें। उनकी यह चेतावनी प्रासंगिक है। क्या भारत या पाकिस्तान युद्ध की लपटों में जले बिना कश्मीर पर अपने-अपने दावों को साकार नहीं करने के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं? नहीं।

यह पहली बार नहीं है, जब बाजवा ने भारत के साथ शांति के पक्ष में बात की है। वह भारत को नहीं, बल्कि धार्मिक अतिवाद को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा मानते हैं। पिछले वर्ष फरवरी में उन्होंने साहसपूर्वक कहा था, 'हम आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आदर्श के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। बाजवा के रचनात्मक दृष्टिकोण का ठोस परिणाम यह हुआ कि पिछले 25 फरवरी को दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा की। अब एक वर्ष से ज़्यादा समय से सीमापार से लगातार गोलीबारी रुकी है, जिसमें दोनों देशों के हज़ारों सैनिक एवं निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवाते थे। यह किसी भी तरह से छोटी उपलब्धि नहीं हे। पिछले वर्ष मार्च में उन्होंने कहा, यह अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का समय है। मौजूदा

यह पहली बार नहीं है, जब बाजवा ने भारत के साथ शांति के पक्ष में बात की है। वह भारत को नहीं बल्कि धार्मिक अतिवाद को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा मानते हैं। गत वर्ष फरवरी में उन्होंने साहसपूर्वक कहा था, 'हम आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह- अस्तित्व के आदर्श के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है।

चुनौतियों के लिए अतीत के विफल समाधानों का लागू करना भोलापन है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत, दोनों देशों से अतीत की कटुता में नहीं फंसने, संघर्ष को बढ़ावा न देने और युद्ध, बीमारी और विनाश के लिए एक और दुश्चक्र में न फंसने का आग्रह किया। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के लाभांश को अपने लोगों तक पहुंचाना तथा शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करना चाहिए।

उन्होंने 02 अप्रैल को अपने ताजा भाषण में इस संदेश को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, 'मेरा मानना है कि यह समय क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व को अपने भावनात्मक और अवधारणात्मक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर इस क्षेत्र के लगभग तीन अरब लोगों के जीवन में शांति एवं समृद्धि लाने के लिए इतिहास की बेढ़ियों को तोड़ने का है।

पाकिस्तान की सेना भारत के साथ शांति की बात क्यों कर रही है? इसका एक कारण तो यह है कि जनरल बाजवा वास्तव में शांतिप्रिय व्यक्ति है। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। दूसरा तथ्य यह है कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपने सैन्य नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मबूर किया है। पाकिस्तान रक्षा मद में करीब दस अरब डॉलर ख़र्च करता है और उसकी सेना में करीब साढ़े पांच लाख हैं। जैसा कि जनरल बाजवा ने स्वयं कहा, 'हमने एक अध्ययन किया है, जिससे हम सेना के आकार को अगले पांच सालों में काफी हद तक कम कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान को अपने नागरिकों की काफी चिंता है, इसलिए हम अपने वादे पूरा करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान अपने आर्थिक और सामरिक लक्ष्यों के चौराहे पर खड़ा है। हमारे पास उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क है - पाकिस्तान से अफग़ानिस्तान फिर अफग़ानिस्तान से मध्य एशियाई गणराज्य और रूस तक। हम पूर्व से पश्चिम (भारत से ईरान) तक संपर्क बनाना चाहते हैं। इससे व्यापार बढ़ेगा और पाकिस्तान सहित क्षेत्र के अन्य देशों को लाभ होगा। और पाकिस्तान एक आधुनिक और दूरदर्शी देश बनेगा। जब उनसे पूछा गया कि वह इसे किस तरह साकार करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि 'यह पाकिस्तान और भारत के लिए आगे बढ़ने का समय है। आइए, हम साथ बैठकर कश्मीर सहित अपने सभी मुद्दों को सुलझाए। हम सबसे पहले विकास चाहते हैं।

भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि पाकिस्तान चीन की कठपुतली बन गया है लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल बाजवा ने ज़ोर देकर कहर कि पाकिस्तान किसी विदेशी शक्ति के खेमे का अनुयायी नहीं बनना चाहता है और अमेरिका सहित सबके साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी स्वतंत्र

बाक़ी पेज 11 पर

समय से पीछे चल रहीं पीडब्ल्यूडी की 30 प्रतिशत परियोजनाएँ

दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मज़बूत के लिए चल रही 17 प्रमुख परियोजनाओं में से लगभग 30 प्रतिशत योजनाएं तय समय सीमा से देरी से चल रही हैं। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से सभी प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें सामने आया है कि लगभग 30 प्रतिशत परियोजनाएं को तय समय से पूरा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, लगभग 70 प्रतिशत परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बेहतर मिली है और उन्हें तय समय से पूर कर लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार की ओर से हाल में पेश किए गए आउटकम बजट 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की पांचवीं स्थिति रिपोर्ट के तहत अनिवार्य रूप से विभिन्न योजनाओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 71 प्रतिशत परियोजनाओं को ट्रैक पर दिखाया गया है और बाकी को प्रमुख संकेतकों के आधार पर ऑफ ट्रैक माना गया है। 17 पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं को आउटकम बजट 2021-22 में शामिल किया गया था और 36 महत्वपूर्ण संकेतकों पर मूल्यांकन किया गया था।

आउटकम बजट के अनुसार, ऑन ट्रैक का मतलब है कि इन मापदंडों पर परियोजनाओं की प्रगति 70 प्रतिशत से अधिक है, जबकि जहां यह लक्ष्य के 70 प्रतिशत से कम है, वहां परियोजना संकेतकों को ऑफ ट्रैक माना जाता है।

बजट रिपोर्ट के अनुसार, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण विभाग, परिवहन विभाग सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से है। विभाग की कुछ ऑन ट्रैक परियोजनाओं में 31 दिसंबर 2021 तक 1.33 लाख सीसीटीवी कैमरे की स्थापना, 2,000 नए मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण (अब कुल 10,500) और 75 हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बसईदारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल के चौड़ीकरण का लगभग 94 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अगस्त 2022 तक सात सैंपल स्ट्रेच के स्ट्रीटस्केपिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि कुछ ऑफ ट्रैक परियोजनाएं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर (आनंद विहार से पीरागढ़ी), उत्तर दक्षिण कॉरिडोर (वजीराबाद से तिलक नगर) और 3.5 किमी लंबे बारापूला-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण (मयूर विहार से सराय कालेखां) है। बारापूला-3 को पूरा करने की समय सीमा अब बढ़कर मार्च 2023 कर दी गई है।❑❑

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनवाएं कार्ड

राजधानी में असंगठित श्रमिक अपने अधिकारों के साथ-साथ दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरुक हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा श्रमिकों द्वारा कराए गए पंजीकरण से लगाया जा सकता है।

साल 2021-22 के दौरान साढ़े छह लाख से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराते हुए अपना कार्ड बनवाया। यह संख्या वर्ष 2020-21 की तुलना में साढ़े तीन गुना अधिक है। वर्ष 2020-21 में दो लाख श्रमिकों ने भी अपना कार्ड नहीं बनवाया था। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का पंजीकरण करके उन्हें अपनी योजनाओं का लाभ देने के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कार्ड बोर्ड का गठन किया हैं बोर्ड से वर्ष 2020-21 में 186909 श्रमिकों ने पंजीकरण कराकर अपना कार्ड बनाया था, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 653426 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं बोर्ड के पास 433917 श्रमिकों के आवेदन लंबित हैं उनका भी कार्ड बनने की स्थिति में राजधानी में पौने 13 लाख श्रमिक पंजीकृत हो जाएंगे। इन श्रमिकों में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले श्रमिक बताए जाते है। यह श्रमिक मज़दूरी के लिए सुबह ही अपने इलाके के चौक चौराहों पर पहुंचते हैं।

पंजीकृत श्रमिकों को मिलता है इन योजनाओं का लाभ

मातृत्व लाभ 30 हजार रुपये (केवल दो बच्चों तक)।

गर्भपात के लिए तीन हजार रुपये वित्तीय सहायता।

60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हज़ार रुपये प्रति माह।

मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम : तीन लाख रुपये।

अक्षमता पेंशन तीन हजार रुपये प्रतिमाह।

दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये तक अनुग्रह राशि।

निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 20 हज़ार रुपये ऋण।

निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए पांच हजार अनुदान।

श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए दस हज़ार वित्तीय सहायता।

प्राकृतिक मृत्यु होने पर एक आश्रित को एक लाख का मुआवज़ा।

कार्य के दौरान मृत्यु पर नामांकित सदस्य को दो लाख का मुआवज़ा।

लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

विवाह के लिए वित्तीय सहायता

पारिवारिक पेंशन।❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

अलविदा ऐ माहे रमज़ान अलविदा

जिस वक्त ये तहरीरें आप तक पहुंचेंगी रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना रुखसत हो रहा होगा और आप ईद का त्यौहार मनाने की तैयारियों में मसरूफ होंगे। ये माहे मुबारक जैसे ही हमारे सरों पर साया फगन हुआ था पुरजोर ईमानी झोंकों की एक बहार सी आ गई थी ज़िक्र व इबादत और शुक्र व हम्द की एक ख़ूबसूरत फिज़ा छा गई थी और चारों ओर से दरुद व सलाम की सदाये आनी शुरू हो गई थी ये दरुद व सलाम इस सरापा ज़ात के लिये था जिसके नूर में इस दुनिया को रोशनी मिली और जिसने किस्मत के मारों के लिये बयाबान की शबें तारीक में कन्दील रहबानी का काम किया। वह ऐसे बशीर व नज़ीर थे जिन्होंने इंसानी दुनिया को खुद साख़्ता और तहरीफशुदा मज़ाहिब और अदयान के जुल्म व सितम हुक्मरानों के जब्र व इसबदाद फख्र व गुरुर और अहानत के दलदल से निकाल कर इंसाफ, मरव्वत, सखावत और भाईचारे का दर्स दिया।

रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिन और रहमतभरी रातें बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई हैं, हमने रमज़ान के चांद का पुरजोश अंदाज़ में स्वागत किया था जिसमें ग़ैर रोज़ेदार बच्चे बूढ़े, जवान मर्द, औरत सब शरीक थे, हिलाल रमज़ान के नज़र आते ही एक दूसरे को खुशखबरी देने लगे थे क्योंकि ये महीना जहां रहमत व मग़फरत का था वही सब्र व तहम्मुल और दोज़ख से निजात का था इस महीने के फज़ायल हदीस की किताबों में कसरत से आये हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ि॰ की हदीस है कि नबी सल्ल॰ ने शाबान की आखरी तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया ''तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है बहुत मुबारक महीना है, इस माह में एक रात हज़ार रातों से बढ़कर है, अल्लाह तआला ने इस माह के रोज़ों को फर्ज़ किया है और इसकी रात के क़याम यानि तरावीह को सवाब की चीज़ बताया है जो शख़्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले वह ऐसा है कि जैसा ग़ैर रमज़ान में सत्तर फर्ज अदा करे, ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है और यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी का है, इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है जो आदमी किसी रोज़ेदार का इफ्तार कराये वह इसके लिये गुनाहों से माफ़ होने और आग से बचने का सबब होगा ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है बीच का हिस्सा मग़फ़रत और आख़िरी हिस्सा आग से निजात का है, रमज़ान का मुबारक महीना शबे क़द्र तरावीह और अशरये आख़री में एतकाफ़ करने के सिलसिले में कसरत से रिवायते हदीस की किताबों में मजकूर है, जो शख़्स इनसे वाक़िफ़ है और इसकी नज़र इस इल्मी ज़ख़ीरे पर है वह ज़िन्दगी के इस सुनहरे मौक़े को ग़नीमत समझता है मिसकीनों को खाना खिलाता है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता है वह अच्छे कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक में ख़ैर व फलाह के काम ज़्यादा होते हैं, रात दिन का कोई ख़्याल नहीं रहता बल्कि जब फक़ीर व मुहताज दरवाज़े पर आया तो इनकी झोली भर दी। यही वजह है कि रमज़ान का महीना ज़िक्र व इबादत, ज़हद व तक़वा का एक आलमी किरदार अदा करता है, हर मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है, जाहिल आलिम से फक़ीर मालदार से कोताह दस्त चाबुक दस्त से गर्ज़ ये कि हर चीज़ में रमज़ान की जलवानुमाई हर शै में माह सयाम की कारफरमाई हर महल और झोपड़ी में रहमतों की हवायें अश्क़ बार चलाने वाले खुदा की तजल्ली और इस माह की खुदराई अहले ख़ैर को पता है कि ये महीना कितना अहम है, इसका जलाल व जमाल क्या है? इंसान जहां कभी भी जाये दुनिया के किसी भी कोने में छिपने की कोशिश करे, रमज़ान का नूरानी बादल इस पर छाया किये रहेगा, पूरा समाज इस अबरे नूर से सैराबी हासिल करता रहेगा, अगर कोई ग़ैर रोज़ेदार है तो इज्तमाईयत से हटकर ज़ाती व इनफरादी तौर पर अपने काम को अंजाम देगा अगर इसे खाने की इच्छा है तो ऐलानिया खाने से शर्माता है और छिपता फिरता है, रमज़ान का रोज़ा एक इज्तमाई और आलमी फिज़ा हमवार करे इसका एक ख़ास माहौल होता है, क़ल्ब में रक़्क़त तारी होती है दिलों में खुशूअ खुजुअ पैदा होता है और दिल के अंदर विभिन्न तरह की इबादतों में शरीक होने का जज़्बा पैदा होता है।

ये मुबारक अय्याम, इबादत व इताअत, दिन रात नेकी व अहसान की वह घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं जिन में मुसलमानों की ये दिली तमन्ना थी कि इनके गुनाह माफ़ कर दिये जायें और वह साबिक़ अला (ख़ैर की तरफ सबबकत करने वाले) बन जायें और जिसमें दुनिया के लवाजमात में लगे रहने वाले हर आदमी की यही आरज़ू थी कि इसकी इबादतों के सवाब दो चंद कर दिये जायें और इसे सालेहीन और अतकिया अबरार वे मुतक्कयों के दर्जे में दाख़िल कर दिया जाये और एक रात में वह सारी खूबियों के मालिक बन जाये जो हज़ार रातों पर मदावमत करने से भी हासिल नहीं होती, एक हदीस पाक में मरवी है कि जो शख़्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नियत से इबादत के लिये खड़ा हो इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। हमने रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल इन तमन्नाओं और आर्जुओं के साथ किया और इसके दिन रात से फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की हैं और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रमज़ान के दिन बहुत कम है और खुशियों के दिन लम्हों में गुज़र जाते हैं।

अब जबकि हम रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कह रहे हैं तो ये बात याद रहे कि हम इस रूहानी फिज़ा और ऐसे इंसानी माहौल को अलविदा कह रहे हैं जिसमें अखवत व मसावात का दौर दौरा होता है, रहमत व मगफ़रत की बादे नसीम चलती है, अफसोस कि दौरे हाज़िर की ज़हरीली फिज़ा ने मुसलमानों में पाई जाने वाली इन विशेषताओं को अगर ख़त्म नहीं किया है तो कम ज़रूर कर किया है और लोगों के दिलों में नफ़ा खोरी और लज्ज़त अंदोज़ी से भर दिया है।

अब रमज़ान मुबारक रुख़सत हो चुका है लेकिन इस पैग़ाम लोगों के दिलों में बालीदगी बख्शेगा क्योंकि ये मश्क व तमरीन का ज़माना है दिलों को सैक़ल करने का वक़्फा है लोगों में जज़्बये हमीअत दीन भरने का लम्हा है, इस महीने की बरकत का ही करिश्मा है कि बुग्ज़ अदावत खत्म हो गई है आपसी नफ़रत व झगड़े खत्म हो गये हैं, आपसी संघर्ष खत्म हो गया है, और मौदत व मुहब्बत पर आधारित सम्बन्ध मज़बूत हुये, फक़ीर व मालदार अफ्तार के वक्त एक दस्तरख्वान पर जमा हुये नमाज़ तरावीह और ज़िक्र व तिलावत में साथ साथ रहे, इन दोनों के बीच आर्थिक दूरी कुछ देर के लिये खत्म हो गई है और इंसानियतसाज इस्लामी मुआशरा कुछ दिनों के लिये वजूद में आ गया जिसकी खुश्बू शामे जां को मुअत्तर करेगी।

ख़ैर की मूसलाधार बारिश करने वाला ये महीना रुख़सत हो गया है, मुसीबतों को दूर करने वाला ये महीना जा रहा है लेकिन इसके आने में अभी देर है इसने हमें ये सबक़ सिखा दिया है कि अगर इस माह में शर व फसाद और फस्क व गुनाह का गलबा न हो तो ज़रूरी हमारी ज़िन्दगियों में इंकलाब आ जायेगा। हमारा रुख तय हो जायेगा और हमारा रुझान बदल जायेगा।

हम रमज़ान मुबारक को एक साल से कम की मुद्दत में सिर्फ ग्यारह माह के लिये अलविदा कह रहे हैं वह हमें अपने बेपनाह अज्र व सवाब से नवाज़े और सभी की उमरो में बरकात दे और तलाफी माफात के लिये दूसरी बार ये सुनहरा अवसर अता फरमाये। रमज़ान की जैसी क़दर करनी चाहिये वैसी क़दर तुमने नहीं की दोबारा इसके आने की उम्मीद में हम इफ्तार करेंगे और जश्न ईदुल फित्र मनायेंगे। हम रमज़ान से हासिल होने वाली नसीहतों को इसके साथ अलविदा नहीं कहेंगे बल्कि उनको हमेशा याद रखेंगे।

हमें आशा है कि ख़ैर के जो आमाल तुमने इस रमज़ान में किये है वह हमारी ज़िन्दगी के लिये मील का पत्थर साबित होंगे और जिन इबरतों को हमने इस माह में हासिल किया है वह हमारी आने वाली ज़िन्दगी में रोशनी चराग़ साबित होंगे, रमज़ानुल मुबारक के बाद ईदुलफित्र बदले का दिन है और पूरे रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिये जज़ा का दिन है, अल्लाह तआला हमारे रोज़ों, नमाज़ों और नेक आमाल को क़बूल फरमायें और रमज़ानुल मुबारक के आमाल की बरकत से पूरे साल आमाले हसना की तौफीक़ अता फरमाये। ❑❑

हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम

8

आबोहवा का लिहाज़

बारको की तामीर में और छावनियां बनाने में हमेशा उम्दा आबोहवा का लिहाज़ रखा जाता था और मकानात के आगे खुले हुये खुशफिज़ा सहन छोड़े जाते थे फौजों के लिये जो शहर आबाद किये गये, मसलन कूफा बसरा, फिसतात आदि में सेहत के लिहाज़ से सड़कें, कूचे और गलियां निहायत वसीअ होती थीं। हज़रत उमर को इसमें इस क़दर अहतमाम था कि मसाहत व वुसअत की तईय्युन भी खुद लिख कर भेजी थी जिनकी तफसील इन शहरों के ज़िक्र में गुज़र चुकी है।

कूच की हालत में फौज के आराम का दिन

फौज जब कूच पर होती थी तो हुक्म था कि हमेशा जुमे के दिन मक़ाम करे और पूरे एक दिन-रात क़याम रखें ताकि लोग दम लें और हथियारों और कपड़ों को दुरुस्त कर ले ये भी ताकीद की थी कि हर रोज़ इसी कदर मसाफत तय करे जिससे थकने न पाये ओर पड़ाव वहीं डाला जाये जहां हर तरह की सुविधायें मौजूद हो, चुनाँचे सअद बिन अली वकास रज़ि॰ को जो फरमान फौजी हिदायतों के मुताल्लिक़ लिखा था और इसमें अहम बातों के साथ इन सारी जुजयात की तफसील भी लिखी।

रुख़सत के क़ायदे

रुख़सत का भी बाक़ायदा प्रबंध था जो फौजें दूर दराज़ मकामात पर तैनात थी इनको साल में एकदफा वरना दो दफा छुट्टी मिलती बल्कि एक बार तो जब उन्होंने एक औरत को अपने शौहर की जुदाई में दर्द नाक शेर पढ़ते सुना तो अफसरों को हुक्म भेज दिये कि कोई शख़्स चार माह से ज़्यादा बाहर रहने पर मजबूर न किया जाये। लेकिन ये आसानियां इसी हद तक थी जहां तक ज़रूरत का तक़ाज़ा था वरना आराम तलबी काहिली ऐशपरस्ती से बचने के लिये सख़्त बंदिशें थी निहायत ताकीद थी कि अहले फौज रकाब के सहारे से संवार न हो नर्म कपड़े न पहने धूपखाना न छोड़े हम्मामो में न नहाये।

फौज का लिबास

इतिहासों से ये पता नहीं चला कि हज़रत उमर रज़ि॰ ने फौज के लिये कोई ख़ास लिबास जिसको वर्दी कहते हैं क़रार दिया था, फौज के नाम इनके जो अहकाम मनकूल हैं इनमें सिर्फ इस कदर है कि लोग अजमी लिबास न पहने लेकिन मालूम होता है कि इस तामील पर चंदा जोर नहीं दिया गया क्योंकि 21वीं हिजरी में जब मिस्र में जिम्मियों पर जज़या मुक़र्रर हुआ तो फौज के कपड़े भी इसमें शामिल थे और वह ये थे कि ऊन का जुबबा लम्बी टोपी या अमामा, मोजा हालांकि अव्वल अव्वल पाजामे और मोज़ा को हज़रत उमर रज़ि॰ ने बतसरीह मना किया था।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ज़रूरी

पुष्कर सिंह धामी

राज्य गठन के बीस वर्ष बाद भाजपा ने दोबारा चुनाव जीतकर मिथक नहीं तोड़ा, बल्कि अपना चुनाव हारे युवा पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से सत्ता की कमान सौंपकर नई परंपरा कायम भी की। उनकी राजनैतिक-आर्थिक चुनौतियों पर उनसे एक विशेष बातचीत हुई, पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- उत्तराखंड के सियासी इतिहास का मिथक तोड़ते हुए भाजपा ने दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाई है। इसे आप कैसे देखते हैं और इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे?

उत्तरः- मैं इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास केन्द्रित नीतियों, हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड की विवेकशील जनता को देना चाहूंगा। जनता के मुख्य सेवक के रूप में मैं तो केवल एक माध्यम था। प्रधानमंत्री जी की दिखाई राह पर चलते हुए हमने राज्य में सर्वस्पर्शी विकास को गति देने का काम किया और यही कारण है कि जनता ने हमें फिर से एक बार सेवा का मौक़ा दिया।

प्रश्नः- खटीमा सीट से स्वयं की पराजय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा के लोगों ने ही 2012 में बीसी खंडूडी की तरह आपको हरवाने का काम किया..?

उत्तरः- मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। हमारे एक-एक कार्यकर्ता ने पूरे समर्पण के साथ इस चुनाव में तय की गई ज़िम्मेदारियों को निभाया है। मैं खटीमा की देवतुल्य जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करता हूं। खटीमा मेरा घर है और मैं खटीमा का बेटा हूं। आने वाले दिनों में खटीमा से मेरा रिश्ता और मज़बूत होगा।

प्रश्नः- चुनाव हारने के बाद भी भाजपा आलाकमान ने ही आप पर भरोसा जताया है। क्या माना जाए कि आलाकमान ने आपके आठ माह के काम और चुनाव में आपकी मेहनत पर अपनी मुहर लगाई है?

उत्तरः- भरोसा तो जनता ने जताया है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं पल प्रतिपल राज्य के विकास का कार्य करूं।

प्रश्नः- अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपकी सरकार पंचवर्षीय योजना पर काम करेगी या फिर प्राथमिकताओं पर समयबद्ध तरीक़े से काम होगा?

उत्तरः- विकास के मामले में उत्तराखंड आज तक वह स्थान हासिल नहीं कर पाया जो उसे हासिल कर लेना चाहिए था। प्रदेश में न तो संभावनाओं की कमी है और न ही क्षमता की। हमारा प्रयास केवल इतना है कि हम इन संभावनाओं और क्षमताओं को वह आकार दे सकें, जिसके आधार प्रदेश की प्रगति हो। हम चाहते हैं कि वर्ष 2025 में जब प्रदेश अपनी स्थापना की रहत जयंत मना रहा हो, तब तक हम उत्तराखंड को हर मानक पर सर्वश्रेष्ठ बना दें।

प्रश्नः- उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में न होने की बात लगभग हर सरकार के समय से सुनी जाती रही है। आपके सहयोगी मंत्रियों ने तो अभी से ही सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग शुरू कर दी है। इस पर आपका क्या कहना है?

उत्तरः- बीती सरकारों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जब से मुख्य सेवक का दायित्व संभाला है तब से सरकार और अधिकारियों के बीच समन्वय निरंतर बेहतर होता जा रहा हे। प्रदेश में अनेक ऐसे कर्मठ अधिकारी भी हैं जो जनसेवा को सर्वोच्च वरीयता देते हुए कार्य कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का उत्साह बढ़ाना सरकारी की ही ज़िम्मेदारी है।

प्रश्नः- सरकारी खज़ाने की हालत खराब बताई जा रही है। अधिकांश पैसा नॉन प्लान पर ही खर्च हो रहा है, हर सरकार कर्ज़ लेकर ही काम करती रही है खज़ाने की आय बढ़ाने और नॉन प्लान का खर्च कम करने के लिए सरकार क्या क़दम उठाने जा रही है?

उत्तरः- प्रधानमंत्री से प्रेरणा पाकर हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। सरकारी खज़ाने को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए हम विभिन्न विकल्पों पर विमर्श कर रहे हैं और हम जल्द ही इस विषय पर राज्य हितकारी रूपरेखा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे।

प्रश्नः- गैरसैंण में स्थायी राजधानी राज्य गठन के बाद से ही अहम मुद्दा रहा है। त्रिवेन्द्र रावत ने इसे तीसरा मंडल बनाने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन इस पर कोई काम आगे नहीं हुआ। आपकी सरकार का इस पर क्या नज़रिया है.?

उत्तरः- गैरसैंण एक स्थान नहीं, बल्कि हम सभी की भावनाओं का केन्द्र है। हम इसके सर्वांगिण विकास के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। यहां विकास के लिए परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ाया जा रहा है और इनमें से कई जल्द ही पूर्ण भी होने वाली हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि गैरसैंण को लोगों की आशाओं के अनुरूप ही विकसित किया जा रहा है।

प्रश्नः- उत्तराखंड में भू-कानून भी एक मुद्दा बन गया है। पिछली सरकार के समय में आपने एक आयोग गठित किया था। अब इस पर सरकार आगे कैसे और क्या-क्या काम करने वाली है?

उत्तरः- इस विषय पर हम बेहद संजीदा हैं और किसी भी स्तर पर प्रदेशवासियों के हितों के साथ समझौता नहीं होने देंगे। भू-कानून को लेकर बनी समिति अपना कार्य कर रही हैं और जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर ही हम नए भू-क़ानून का ख़ाक़ा तैयार करेंगे।

प्रश्नः- राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या हैं पर्वतीय जनपदों से मैदानी जनपदों की ओर पलायन होता रहा है। रोज़गार की तलाश में युवा पहाड़ छोड़ रहे हैं। इस दिशा में सरकार क्या ठोस क़दम उठाने जा रही है?

उत्तरः- मैं इससे इंकार नहीं कर रहा कि पहाड़ से पलायन एक चिंता का विषय है लेकिन आपको बता दूं कि अब हालात बदल रहे हैं। राज्य में अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, पशुपालन, पर्यटन, साहसिक खेलों और कई दूसरे माध्यमों से पहाड़ का युवा अब न केवल स्वयं आजीविका अर्जित कर रहा बल्कि युवाओं को रोज़गार भी प्रदान कर रहा। हम जहां एक ओर सरकारी सेवाओं में रिक्त स्थान भरकर युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं स्व-रोज़गार को भी बढ़ावे देने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस समस्या का समाधान अब दूर नहीं है।

प्रश्नः- 2026 में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन होना है। माना जा रहा है कि नए परिसीमन में पर्वतीय जिलों में सीटें और कम हो जाएंगी और मैदानी इलाक़े का वर्चस्व हो जाएगा। इस बारे में सरकार की क्या सोच है.?

उत्तरः- जनता ने हमें उत्तराखंड विकास का दायित्व दिया है। चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी। लक्ष्य केवल यह कि प्रदेश के प्रत्येक भाग में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर

बाक़ी पेज 11 पर

बीएसएफ पर पैरलल पुलिस होने का इल्ज़ाम ग़लत : पंकज कुमार सिंह

प्रश्नःबीएसएफ का जुरिस्डिक्शन 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया हैं कहा जा रहाा हे कि यह अब पैरलल पुलिस बन रही है। इस विषय पर आप क्या कहते हैं.?

उत्तरः- इस विषय में काफी भ्रांतियां है। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का दायरा 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया है। इसके लिए मात्र दो कानूनों के तीन क्लॉज में बदलाव किया गया है पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इन टू इंडिया एक्ट के तीन क्लॉज में ये परिवर्तन किए गए हैं। सीआरपीसी में जो बदलाव हुआ है, उसके अंतर्गत हम सर्च कर सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं। यह दायरा किसी अपराधी पर लागू नहीं होगा बल्कि सीमा क्षेत्र से अवांछनीय तरीके से इंफिल्ट्रेशन करने वाले पर लागू होगा। यह इसलिए बनाया गया है क्योंकि सीमा क्षेत्र से इंफिल्ट्रेशन (घुसपैठ) ज़्यादा है, जो वहां की लोकल डेमोग्राफी बदल देता है। इससे घुसपैठ रुकेगा। सरकार ने सोचा है कि शायद इससे राज्य पुलिस बल को मदद मिलेगी। यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अभी भी मुकदमे में इन्वेस्टिेशन का दायित्व भी राज्य पुलिस का है। सीमा पुलिस बल का यहां काम अवांछनीय व्यक्ति को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंपने का है, उससे आगे की कार्रवाई राज्य की स्थानीय पुलिस करेगी।

प्रश्नः- हमारे देश की सीमाएं बहुत व्यापक हैं और बीएसएफ वहां लगातार तैनात रही है चीन अपने चरवाहों के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहा है इसलिए कि उसकी सेना के स्थानीय लोगों से संबंध बेहतर हें आप लोग क्या कर रहे हैं?

उत्तरः- सीमा सुरक्षा बल प्रथम रक्षा पंक्ति के साथ और भी बहुत कुछ है। चाहे बांग्लादेश की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा। हम देश की सुरक्षा केवल बंदूकर तानकर और सर्विलांस से ही नहीं करते। इसके साथ हम सिविक कार्यों के ज़रिए सीमा के नज़दीक रहने वाले लोगों से अच्छा सामंजस्य बनाते हैं। उनकी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे मेडिकल कैंप लगना, रोज़गार प्रशिक्षण देना, छोटे बांध बनवा देना, उनकी डिस्पेंसरी में दवाएं, उपलब्ध करवा देना। सुंदर वन डेल्टा क्षेत्र में हम बोट एंबुलेंस चला रहे हैं, जो नजदीकी गांवों में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कोविड में जागरुकता और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलाए। हमारा सोचना है कि सीमा के नज़दीक जितनी भी बसावट है, अगर ये लोग हमारे आंख और कान बने तो हमारा काम सुगम हो सकता है।

प्रश्नः- आपको क्या लगता है कि सीमा सुरक्षा बल इस वक्त पूरी तरह से डिवलेप हो चुका है हर चुनौती का सामना करने के लिए.?

उत्तरः- किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को काउंटर करने के लिए हमें अपने लोगों को परिपक्व और प्रशिक्षित करना होगा। चाहे वह हथियारों के बारे में हो या टेक्टिस के बारे में, या फील्ड के ज्ञान के बारे में हो, व्यक्ति को हर तरह की तकनीक से जोड़ना पड़ेगा।

प्रश्नः- जेसलमैर में वॉर म्यूजियम और रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने का उद्देश्य क्या है?

उत्तरः- आज तक चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो या छोटे मोटे यप में जितनी भी सीमा से संबंधित घटनाएं होती हैं, वहां पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की संख्या कम नहीं है। जिन सैनिकों ने अपनी बहादुरी से देश की अखंडता को मज़बूत बनाया है, ऐसे वीरों को याद करने के लिए और ताकि वे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, वॉर म्यूजियम बना रहे हैं। हमने अटारी में भी ऐसा म्यूजियम बनाया है। गुजरात में बनाया है। वहां शहीदों और वीर योद्धाओं की तस्वीरों के साथ उनकी गाथा लिखी है। रिट्रीट सेरेमनी होती है वो देश प्रेम को दिखाती है। लोग उसे देखकर गर्व की भावना से भर उठाते हैं। हम हुसैनी वाला में ऐसी सेरेमनी करते हैं। अटारी में दोनों देशों की सेना मिलकर झंडा उतारती हैं, बांग्लादेश सीमा पर की जाती है। □□

असमानता की चौड़ी होती खाई

अंतरार्ष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान गरीबी स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। आंकड़ों के मुताबिक, भारत 2019 में बेहद गरीब यानि सबसे कम क्रय शक्ति वाले लोगों का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी नीचे रहा। वहीं, प्रति व्यक्ति खरीद क्षमता (पीपीपी) 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति रोजाना आंकी गई। ग़ौरतलब है कि वर्ष 2020 के दौरान भी यह रफ्तार उसी स्तर पर बनी रही। केन्द्र सरकार की ग़रीब कल्याण योजना का फायदा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 80 करोड़ लोगों को मिला है। यह योजना 2016 में गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इसी दौरान देश में बेरोज़गारी तेजी से बढ़ती चली गई। महामारी को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी और अन्य प्रतिबंधों के कारण रोज़गार छिनने से निम्न आय वर्ग में आने वाले करोड़ों लोगों की हालत पिछले दो सालों में ज़्यादा ख़राब हुई है।

इस वर्ष की वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दुनिया में असमानता तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार की वजह से आय और संपत्ति दोनों में व्यापक रूप से असमानता पैदा हो रही है। शोध कर्ताओं के अनुसार आज दुनिया एक बार फिर कमोबेश वैसी ही स्थिति में आ गई है, जैसे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्यवाद के चरम के समय थी। इसीलिए अर्थशास्त्री इसे दो सौ वर्ष पहले जैसी गैर बराबरी की संज्ञा दे रहे हैं। बताया जाता है कि तब भी शीर्ष दस प्रतिशत लोग ही कुल आय का आठ प्रतिशत हिस्सा अर्जित करते थे, जबकि निम्न आए वाले पचास प्रतिशत लोग सिर्फ पांच से पन्द्रह प्रतिशत। इसलिए देखा जाए तो समाज में आर्थिक असमानता की जड़ें पहले से ही गहरी रही हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के विकास के साथ यह असमानता कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इससे दुनियाभर के देशों में आर्थिक और सामाजिक संतुलन गड़बड़ा भी रहा है।

निवेश बैंकिंग कंपनी क्रेडिट सूइस ग्रुप एजी के मुताबिक साल 2010 में देश के एक प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का चालीस प्रतिशत हिस्सा था, जो 2016 में बढ़कर 58. 4 प्रतिशत हो गया । इसी तरह 2010 में दस प्रतिशत लोगों के पास देश की 68.8 प्रतिशत संपत्ति थी, लेकिन 2016 में बढ़कर यह 80.7 प्रतिशत हो गई। यह बात पर गौर करने वाली है कि पिछले दो सालों में ग़रीबों की अतिरिक्त दस प्रतिशत संपत्ति छन गई। ज़ाहिर है, इसके पीछे सरकारों की नीतियां बड़ा कारण रही हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की हालत को सुधारने की जो कवायदे केन्द्र व राज्य सरकारों के ज़रिए की गईं, लगता है वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जबकि केन्द्र सरकार का दावा है कि पिछले आठ सालों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पर भ्रष्टाचार के मामले में वैश्विक सूचकांक में हम किस पायदान पर हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत के महज़ एक प्रतिशत लोगों के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। दुनिया के कुल करोड़पतियों में से दो प्रतिशत करोड़पति भारत में रहते हैं और पांच प्रतिशत अरबपति। इसी तरह मुंबई में सबसे अधिक एक हज़ार तीन सौ चालीस धनकुबेर रहते हैं, यदि यही रफ्तार जारी रही तो महज़ दो सालों में दस हज़ार से अधिक नए धनपति इस कतार में और जुड़ जाएंगे। ज़ाहिर है जैसे जैसे देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वैसे-वैसे ग़रीबों और अमीरों दोनों की तादाद बढ़ती जा रही है। केन्द्र सरकार का कहना है कि धनपतियों की तादाद बढ़ने से आयकर के संग्रहण में वृद्धि हुई है। इससे विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद मिलती है। आने वाले दस सालों में भारत में अति धनाढ्यों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर, ग़रीबों, बीमारों और असहायों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, वह चिंता का विषय है। इस बढ़ती गैरबराबरी से आर्थिक और सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा और नई-नई समस्याएं सामने आएंगी।

शहरों और महानगरों में निर्माण की जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उससे शहरों में प्राकृतिक संसाधनों की खपत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दुसरी ओर साफ पानी, हवा, सस्ता खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ेंगी। इस पर केन्द्र और राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में देश में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का काम जोरों पर है। सरकार ने नए शहरों के निर्माण का जो ख़ाका तैयार किया है, उससे गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा और शहरी जीवन में असमानता बढ़ेगी। इसका असर सामाजिक समरसता, समुचित शिक्षा की स्वास्थ्य जैसे आवश्यक सामाजिक पहलुओं पर पड़ना तय है। शिक्षा और स्वास्थ्य से ताल्लुक रखने वाले संसाधन जिस तरह महंगे होते जा रहे हैं, उससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। समाज का सबसे ग़रीब तबक़ा नई-नई बीमारियों से घिर रहा है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे बीमारू राज्यों में ग़रीबों की हालत किससे छिपी है? कोरोना काल में मुफ्त राशन और सिलेंडर मुहैया कराने से गरीबों को कुछ राहत ज़रूर मिली, लेकिन यह समस्या का स्थायी हल नहीं कहा जा सकता।

समस्या यह है कि विकास के नाम पर आज तक जितनी योजनाएं बनती आई हैं, उनमें ग़रीबी मिटाने का बुनियाद लक्ष्य ग़ायब ही रहा है। पिछले वर्ष दशकों में केन्द्र और राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, ग़रीबों के मुद्दे हाशिए पर ही रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में आज भी हम दयनीय स्थिति में ही हैं। प्रश्न तो इस बात का है कि अगर विकास योजनाओं में ग़रीबों को केन्द्र में रखा जाता है तो फिर देश में ग़रीबों की तादाद कम क्यों नहीं हो रही है? पिछले कई दशकों से गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी है। इसीलिए कि गांवों में रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का आज तक भी कोई मज़बूत ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है हालांकि दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, बंगलुरू की तरह ही कोलकाता, हैदराबाद और इनके उनगर अस्तित्व में आए हैं। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में इन शहरों में जिस तेजी से अमीर तबक़ा सामने आया है और इन शहरों की एक नई पहचान बन गई है, वह कहीं न कहीं हैरानी पैदा करता है। थोड़े से समय में ध नकुबेरों की बढ़ती तादाद से साफ है कि सरकारों की नीतियां अमीरों और ग़रीबी के बीच खाई और चौड़ी करने वाली ही रही है।

बेहतर होता कि केन्द्र और राज्य सरकारें मेट्रो शहर बसाने की जगह गांवों के विकास और नए ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण की योजना बनातीं, ताकि गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन पर रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार मेट्रो गांव बनाने की बात कही है। लेकिन इस मैट्रो गांव का स्वरूप कैसा होगा, यह अपने वाले समय में पता चलेगा। यदि मेट्रो गांव के निर्माण की बात केन्द्र सरकार मुकम्मल योजना के साथ लाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भारत में बढ़ती असमानता, ग़रीबी, अशिक्षा, पलायन और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में बड़ा क़दम होगा। इससे गांवों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी रुकेगा और गांव में ही लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त भी हो सकेगा। ❑❑

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्लीनिकल प्रयोगशाला का महत्व

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्लीनिकल प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए डाक्टर मरीज़ों का विभिन्न तरह की जांच कराते हैं, ताकि असली मर्ज़ और उसकी स्थिति का पता चल सके। ऐसे में सही इलाज और दवा के लिए क्लिनिकल प्रयोगशाला की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसी प्रयोगशालाओं पर काम करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों को चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट (एमएलटी) कहा जाता है। एमएलटी की पढ़ाई में बायो केमेस्ट्री, माइक्रोबायलॉजी और ब्लड बैंकिंग शामिल हैं। एमएलटी शरीर में खून, खून के प्रकार, सेल और अन्य की अवस्थाओं का विश्लेषण करता है।

नेचर ऑफ वर्क

मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डाक्टरों के निर्देश पर काम करते हैं। उपकरणों के रख रखाव और कई तरह के काम इनके ज़िम्मे होता है। लेबोरेट्री में नमूनों की जांच और विश्लेषण में काम आने वाला घोल भी लैब टेक्नीशियन ही बनाते हैं। इन्हें मेडिकल साइंस के साथ साथ लैब सुरक्षा नियमों और ज़रूरतों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लैब टेक्नीशियन नमूनों की जांच का काम करते हैं, लेकिन वे इसके परिणामों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। नमूनों के परिणामों का विश्लेषण पैथोलॉजिस्ट या लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही कर सकता है। जांच के दौरान एमएलटी कुछ सैंपलों को आगे की जांच या फिर ज़रूरत के अनुसार उन्हें सुरक्षित भी रख लेता है। एमएलटी का काम बहुत ही ज़िम्मेदारी और चुनौती भरा होता है। इसमें धैर्य और निपुणता की बड़ी आवश्यकता होती है। जमा किए गए डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की भी ज़िम्मेदारी उसकी होती है।

कोर्स के दौरान क्या पढ़ें

विशेषज्ञों के मुताबिक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं मास्टर्स के दौरान बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इनवाइरन्मेंट एण्ड बोयोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलॉजी एवं अस्पताल प्रशिक्षण की पढ़ाई की जाती है।

कोर्स एवं योग्यता

सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (सीएमएलटी) यह छह महीने का कोर्स है जिसके लिए योग्यता है 10वीं पास। वहीं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। इस कोर्स की अवधि है एक साल। 12वीं में प्रमुख विषय के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (पीसीबी) तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (पीसीएम) के साथ पास होना अनिवार्य है। बीएससी इन एमएलटी के लिए 12वीं विज्ञान विषयों के साथ तो उत्तीर्ण होना ज़रूरी है ही साथ ही इस कोर्स की अवधि है तीन वर्ष। (एमएलटी) प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी के पास पहले हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद दो साल का एसोसिएट प्रोग्राम होना होता हैं यह प्रोग्राम कम्युनिटी कॉलेज, टेक्निकल स्कूल, वोकेशनल स्कूल या विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है।

क्या है वेतनमान

सामान्य तौर पर एक एमएलटी का वेतन दस हजार से शुरू होता है जबकि पैथोलाजिस्ट को तीस हजार से चालीस हजार तक सैलरी मिल जाती है। साथ ही योग्यता और तजुर्बे के आधार पर उनके वेतन में इज़ाफा होता चला जाता है। देश के साथ साथ विदेशों में भी इनकी ख़ासी डिमांड है।

प्रमुख संस्थान

क्रैडल ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीटयूट, नई दिल्ली। www.cmi-hm.com

डेल्ही पारामेडिकल एण्ड मैनेमेंट इंस्टीटयूट (डीपीएमआई) नई दिल्ली।

www.dpmiindia.com

हिमालयन यूनिवर्सिटी अरूणाचल प्रदेश

www.himalayanuniversity.com

शिवालिक इंस्टीटयूट ऑफ पारामेडिकल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़

www.shivalikinstitue.org

डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।

www.amu.ac.in ❑❑

इस्लामी दुनिया

कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना स्थायी शांति नहीं : शहबाज़

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि कश्मीर विवाद के न्यायसंगत समाधान के बिना स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती। शहबाज़ ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में तब शपथ ली थी जब उनके पूर्ववर्ती इमरान ख़ान को अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए अपदस्थ कर दिया गया था।

सिंगापुर के मंत्री बिन उस्मान की अनुराग ठाकुर से मुलाकात

सिंगापुर के मंत्री मोहम्मद मलिकी बिन उस्मान ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और अपने-अपने देशों मे डिजिटल मीडिया विनियमन समेत व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। सिंगापुर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री उस्मान ने ठाकुर को सिगांपुर में डिटिजल मीडिया और डिजिटल मंचों के नियामक ढांचे के बारे में अवगत कराया वही ठाकुर ने विनिमयन की त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया।

पाक नौका से 280 करोड़ की हेराइन बरामद , 9 गिरफ्तार

भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एसटीएस) ने राज्य के तट के पास अरब सागर में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा है जिससे 280 करोड़ रुपये मूल्य की हेराईन बरामद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तटरक्षक बल को पाकिस्तानी नौका पर कुछ गोलियां चलानी पड़ीं क्योंकि इंटरसैप्टर पोत द्वारा 2 से 3 सदस्य मामूली रूप से घायल हो गए। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान नौका और उसके चालक दल के सदस्यों को आगे की जांच के लिए गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह ले जाया गया।

ईरान से कांडला पोर्ट पहुंची 1439 करोड़ की हेराईन ज़ब्त

कांडला बंदरगाह के पास कंटेनर में छिपाकर रखी 205.6 किलो हिरोइन की खेप बरामद की गई है। इसका मूल्य 1439 करोड़ रुपये बताया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बताया कि इस सिलसिले में पंजाब से एक आयातक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के जीडीपी आशीष भाटिया ने बताया, ईरान के अंदर अब्बास बंदरगाह से पिछले वर्ष आए 17 कंटेनरों में से एक में यह खेप बरामद हुई है। इसे उत्तराखंड की एक कंपनी ने आयात किया था। कहा गया था कि इसमें 'जिप्सम पाउडर' है।

ईदुल फ़ित्र के अहकाम व मसायल

प्रत्येक धर्म में त्यौहारों पर कोई पाबंदियां या कोई मुनज्ज़म तरीका नहीं होता त्यौहारों को मनाने का, पर हमारे दीन-ए-इस्लाम में ईद को मनाने का एक मुकम्मल तरीक़ा बताया गया है, इन्शाअल्लाह अगर इस पर अमल करके ईद मनाएंगे तो अल्लाह तआला हमारे इस अमल से खुश होगा। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, आज के दिन रोज़ा न रखना इबादत है।

फितराना की मिक़्दार

ईद के दिन सदक़ा फितर अदा करें जो साहबे निसाब (धनाढ्य, मालदार) पर वाजिब है। हदीस शरीफ में आता है कि सदक़ा फित्र रोज़ों को गंदगी भरी उलूम जलूल हरकतों, बातों से पवित्र करने के लिए और मिस्कीनों की रोज़ी के लिए मुक़र्रर किया गया है। (अबू दाऊद)

हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर (रजि॰) से रिवायत है कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सदक़ातुल फित्र को ज़रूरी क़रार दिया। (फिकस) एक साअ खजूरें और इसी क़दर जो दिए जाएं गुलाम और आज़ाद मर्द और औरत और हर छोटे बड़े मुसलमान की तरफ से और नमाज़ ईद के लिए लोगों को जाने से पहले अदा करने का हुक्म फरमाया। (मिश्कात पेज॰ 160, बहवाला बुख़ारी व मुस्लिम)

किस पर वाजिब है

सदक़ा फितर उस व्यक्ति पर वाजिब है जिस पर ज़कात फर्ज है यानि साढ़े बावन तौला चांदी या इसकी कीमत उसकी मिल्कियत में (मालिक) हो। या अगर सोना चांदी और नक़द रक़म न हो और ज़रूरत से अधिक सामान मौजूद हो जिसकी कीमत साढ़े बावन तौला चांदी बन सकती हो तो उस पर भी सदक़ा अल फित्र वाजिब है, ज़कात फर्ज़ होने के लिए यह ज़रूरी है कि माल निसाब (सम्पत्ति) पर चांद के हिसाब से एक साल गुज़र जाए लेकिन सदक़ा अलफित्र वाजिब होने के लिए यह शर्त नहीं है, अगर रमज़ान की तीस तारीख़ को किसी के पास माल आ गया तो ईदुल फित्र की सुबह सादिक़ होते ही इस पर सदक़ा फित्र वाजिब हो जाएगा।

रोज़ों की क़बूलियत

सदक़ा अल फित्र अदा कर देने से रोज़ों की क़बूलियात की राह में कोई अटकाने वाली चीज़ बाक़ी नहीं रह जाती है।

अदायगी फितराना

सदक़ा फितर बालिग़ औरत पर अपनी तरफ से देना वाजिब है। शोहर के ज़िम्मे उसका सदक़ा फितर अदा करना ज़रूरी नहीं और जो नाबालिग़ औलाद है उसकी तरफ से वालिद पर सदक़ा फितर देना वाजिब है, बच्चों की वालिदा (माँ) के ज़िम्मे बच्चों का सदक़ा फितर देना लाज़िम नहीं है।

जौ और गेहूँ इत्यादि

हुज़ूर अक़्दस (सल्ल॰) के ज़माने में जौ और गेहूं इत्यादि नाप कर बेचा जाता था और इन चीज़ों को तोलने के बजाय नापने का रिवाज़ था इस ज़माने में नापने का जो एक पैमाना था उसी के हिसाब से हदीस शरीफ़ में सदक़ा फितर की मिक़्दार (मात्रा) बतायी है एक साअ कुछ ऊपर साढ़े तीन सेर का होता था।

वक़्त अदायगी

सदक़ा फितर ईद के दिन की सुबह के शुरू होने पर वाजिब होता है, अगर कोई व्यक्ति इससे पहले मर जाए तो उसकी तरफ से सदक़ा फितर वाजिब नहीं। सदक़ातुल फितर ईद से पहले भी अदा किया जा सकता है। अगर पहले अदा न किया तो ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाएगा अगर किसी ने नमाज़ ईद से पहले या बाद न किया तो साक़ित (समाप्त) न होगा उसकी अदायगी बराबर ज़िम्मे बनी रहेगी। जो बच्चा ईदुल फितर की सुबह सादिक़ हो जाने के बाद पैदा हुआ हो उसकी तरफ से सदक़ा फितर देना वाजिब नहीं।

नाबालिग़ शख़्स

अगर किसी नाबालिग़ की मिल्कियत में खुद अपना माल हो जिस पर सदक़ा अल फितर वाजिब होता है तो उसका वारिस उसी के माल से इसका सदक़ा फितर अदा करे इस स्थिति में अपने माल से देना वाजिब नहीं।

रिश्तेदारों को ज़कात और सदक़ा फितर देना जाइज़ है इनको देने से दोहरा सवाब होता है क्योंकि इसमें सिलारहमी भी हो जाती है।

ग़रीब नौकरों को अदायगी

अपने ग़रीब नौकरों को भी ज़कात और सदक़ा फितर दे सकते हैं मगर उनकी तंख़्वाह में लगाना दुरूस्त नहीं।

दूसरे रिश्तेदारों को अदायगी

अपनी औलाद को या मां बाप और नाना नानी और दादा दादी को ज़कात और सदक़ा फितर नहीं दे सकते, अलबत्ता दूसरे रिश्तेदारों उदाहरणार्थ भाई, बहन, चचा, मामू, ख़ाला आदि को दे सकते हैं। शोहर बीवी को बीवी शौहर को सदक़ा फितर दे तो अदायगी नहीं होगी।

किन को देना जाइज़ नहीं

जिन पर ज़कात खुद वाजिब हो या वाजिब होने की सीमा के अनुसार उसके पास माल हो या ज़रूरत से अधिक सामान हो जिसकी वजह से सदक़ा फितर दे सकते हैं।

एक व्यक्ति का सदक़ा फितर एक मोहताज को दे देना या थोड़ा थोड़ा करके कई मोहताजों को दे देना दोनों सूरतें (स्थितियां) जाइज़ है और यह भी जायज़ है कि कुछ आदमियों का सदक़ा फितर एक ही मोहताज को दे दिया जाए।

रोज़े न रखने की स्थिति में भी अदायगी है

अगर किसी बालिग़ पुरूष स्त्री ने किसी वजह से रोज़े न रखे तब भी सदक़ा फितर का निसाब होने पर सदक़ा फितर की अदायगी वाजिब है सदक़ा फितर में जौ या गेहूं या कोई और वैकल्पिक अनाज या नक़द कीमत भी दी जा सकती है बल्कि इसका देना अफज़ल है।

ईद की सुन्नतें

शरीअत के अनुसार अपनी आराइश करना, ग़ुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना जो पास मौजूद हों, खुश्बू लगाना, सुबह को बहुत सवेरे उठना, ईदगाह में सवेरे जाना, ईदगाह जाने से पहले ईदुल फितर में कोई मिठी चीज जैसे छुआरा आदि खाना और ईदुल अज़्हा में नमाज़ से पहले कोई चीज़ न खाना बल्कि कुर्बानी का गोश्त खाना। ईदगाह जाने से पहले सदक़ा फितर देना, ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ना यानि शहर की मस्जिद में बिला उज़्र न पढ़ना, जिस रास्ते से जाए उसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना, पैदल जाना, रास्ते में तकबीर तश्रीक, 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द' पढ़ते हुए जाना। (आलमगिरी 1\149)

ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

नीयत इस तरह करें : दो रकअत नमाज़ वाजिब ईदुल फितर छह जाइद तकबीरों के साथ, पेश ईमाम के पीछे, मुंह मेरा काबे शरीफ़ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे और सना के बाद तीन तकबीरें होंगी। इस तरह कि अल्लाह अकबर कह कर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। तीसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाएं और बांध लें, इसके बाद नियमनुसार सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर पहली रकअत पूरी करें और दूसरी रकअत के लिए खड़े होकर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद रूकू में जाने से पहले तीन जाइद (अधिक) तकबीरें कहें, इस तरह कि पहली तकबीर कह कर हाथ कानों तक उठाएं और नीचे छोड़ दें दूसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाए और छोड़ दें, तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें, चौथी तकबीर कहते हुए बग़ैर कानों तक हाथ उठाए रूकू में चले जाएं और हस्बे दस्तूर नमाज़ पूरी कर ली जाए। (आलमगिरी 1\150)

कुछ मसायल

मसअला:- ईद के दिन कब्रिस्तान जाने में कोई मज़ायका (मनाही) नहीं लेकिन इसका अलतजाम करना और न जाने वालों को हकीर समझना या उस पर ताअन करना उचित नहीं। (फतावी महमूदिया, 2\277)

मसअला:- ईद की नमाज़ के बाद दुआ मांगना तमाम नमाज़ों की तरह मसनून व मुस्तहब है मगर ईद के खुत्बा के बाद दुआ मांगना साबित नहीं है। (आलमगिरी 1\152)

मसअला:- अगर ईद जुमे के रोज़ वाक्अ हो तो (ईद और जुमां) दोनों की नमाज़ लाज़िम है अव्वल वाजिब दूसरी फर्ज़।

मसअला:- कुछ बेइल्म जुमे के दिन ईद होने को नामुबारक समझते हैं यह ख़्याल बिल्कुल बातिल है बल्कि इसमें दो बरकतें जमा हो जाएंगी।

मसअला:- खुत्बा ईद का सुन्नत है और हाज़िरीन पर इसका सुनना वाजिब है इस वक़्त बोलना, चलना या नमाज़ पढ़ना हराम है। ❑❑

क्या शशि थरूर रंग बदल सकते हैं

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के टीएमसी में जाने की चर्चा पहले थी। पिछले दिनों केरल भाजपा के एक प्रमुख नेता जो मोदी सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वे थरूर से मिलने पहुंचे और थरूर को भाजपा में शामिल होने का आमंण दिया। यह कहते हुए कि 'तिरुवंतपुरम जहां से थरूर सांसद हैं वहां भाजपा तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में भी भाजपा को यहां 316142 वोट आए थे। सो, अगर 24 का चुनाव उन्हें तिरुवंतपुरम से ही जीतना है तो उनके समक्ष भाजपा से अच्छा और कोई विकल्प नहीं, पूर्व में भी कई मौक़ों पर थरूर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं जो इस धारणा को पुख़्ता करती है कि थरूर को वैसे भी भाजपा से कोई एलर्जी नहीं। समझा जाता है कि भाजपा की ओर से थरूर को यह भी आश्वासन मिला है कि 'वे चाहे तो नई दिल्ली संसदीय सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं जाहिर है इन दिनों थरूर का दिल भगवा-भगवा है।

आलमे इस्लाम में ईदुल फित्र मनाने का तरीके

ईदुल फितर कौम का बड़ा त्योहार है जो पूरे आलमे इस्लाम में खुशी और परम्परा के साथ मनाया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादतों का फल मुसलमानों को इसी ईदुल फितर की सूरत में मिलता है। तब ही उसे मनाने के लिए दुनियाभर के मुसलमान अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर तैयारियां कोशिशें करते हैं। ईदुल फितर के हवाले से अगरचे विभिन्न मामले फर्ज़ दुनियाभर में एक जैसे हैं उदाहरणार्थ –नमाज़ ईदुल फितर की अदायगी, सदक़ा फितर देना, नए लिबास, खूश्बू लगाना, रिश्तेदारों मित्रों के घर जाना, दोस्तों से मेल मुलाक़ात वगैरहा लेकिन स्थानीय संस्कृति के प्रभाव धार्मिक त्योहारों से भी झलकते हैं। विभिन्न देशों में कुछ परम्पराएं रिवाज़ भी देखने को मिलते हैं। यूं हर क्षेत्र की ईद दूसरों से कुछ दुनियावी आधार पर अलग अलग सी भी हो जाती है और यह भिन्नता जीवन के स्टाइल से लेकर लिबास और खाने पीने तक में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर भारत पाक में ईद के अवसर पर औरतें मर्दों के साथ नमाज़ ईद के इज्तमा में भाग नहीं लेती हैं। विभिन्न इस्लामिक देशों में ईद कैसे मनायी जाती है और इस अवसर पर क्या अहतमाम किया जाता है इसका एक संक्षिप्त जायज़ा पेश है:-

मिस्र:- मिस्र में ईद के अवसर पर सरकारी छुटिटयां होती हैं सरकार व निजी इदारों, स्कूलों में छुटटी होने के साथ साथ रेस्त्रां और स्टोर्स भी बन्द रहते हैं। मिस्री मुसलमान ईद के दिन का आगाज़ हल्के फुल्के नाश्ते से करते हैं जिसके बाद लोग घर की औरतें और बच्चों के साथ ईदगाह जाते हैं। नमाज़ ईद के बाद खुत्बा होता है मिस्र के कल्चर के अनुसार ईद के पहले दिन लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं। घरों मे तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं और पूरा खानदान एक दस्तरख्वान पर खाना खाता है लोग एक दूसरे से ईद मिलते हुए ईद मुबारक या ईद सईद के शब्द बोलते हैं, ईद के शेष दो दिन आम तौर पर किसी तफरीह स्थान उदाहरणार्थ, पार्क, नील नदी के किनारे या फिर शर्म अल शेख़ में पिकनिक मनाते हुए गुज़ारते हैं। इस्लामी परम्परा के अनुसार मिस्र के लोग भी ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं और औरतें (मां, बहनों, बीवियों और बेटियों) को तोहफे देने का रिवाज़ भी आम है। बच्चों को इदिदयां दीं जाती हैं। ईददी दरअसल कुछ पैसे होते हैं जो त्योहार के मोक़े पर बड़ों की तरफ से बच्चों को दिए जाते हैं जिसे भारत में ईदी कहते हैं। बच्चों की तफरी खाने पीने का आधार इसी ईदी पर होता है। मिस्र में खाने विशेषकर मीठे के हवाले से ईदुल फितर की ख़ास सौग़ात 'काअक' नामक बिस्कुट है जिनको मूंगफलियों से तैयार किया जाता है और इसके ऊपर शूगर पाउडर का छिड़काव होता है।

इंडोनेशिया:- ईदुल फित्र का त्योहार इन दोनों देशों विशेषकर इंडोनेशिया में अलग ही तरह से मनाया जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंडोनेशी जनता इस ईद को इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार समझते हैं जो रमज़ानुल मुबारक के समापन पर मुसलमानों के लिए इनाम के तौर पर होता है। यहां ईद को 'ईदुल फितरी या लिब्रान कहते हैं।' ईद के अवसर पर इंडोनेशिया और मलेशिया में सरकारी छुटिटयां होती हैं जब कि इंडोनेशिया में लेबर विभाग के क़ानून के अनुसार देश में मौजूद सारे सरकारी व निजी इदारों की ओर से कर्मचारियों को विशेष बोनस दिए जाते हैं। इस बोनस को 'तन्हा गहन हरीराया' कहा जाता है। यह बोनस एक महीने के वेतन के बराबर होता है और अगर कोई कम्पनी इस क़ानून पर अमल नहीं करती तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाती है और कम्पनी को जुर्माना भरना पड़ता है। कानून के अनुसार बोनस की रक़म सूबे और कम्पनी के लिहाज़ से भिन्न भिन्न होती है।

मलेशिया में ईद को 'हरी राया पोसा' कहा जाता है। जिस का मतलब है कि इस दिन को जोश व खरोश से मनाया जाए। इन दोनों देशों में जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, शॉपिंग माल्स और बाज़ारों में भी रौनक़ बढ़ने लगती है लोग नए कपड़ों, मेहमाननवाज़ी के लिए सामान की खरीदारी करते हैं इस अवसर पर कई फैक्ट्रियां अपने कर्मचारियों को छुटटी भी देती हैं ताकि वह ईद की शॉपिंग तरीके से कर सकें। इंडोनेशिया और मलेशिया में एक और परम्परा 'मोदीक' की भी है जिसके अनुसार ईद से पहले लोग अपने मित्रों रिश्तेदारों और उनसे अपनी जानी अनजानी ग़लतियों की माफ़ी मांगते हैं जिसका उद्देश्य यह होता है कि ईद के अवसर पर लोग दिलों में कोई गिला शिकवा न रखें और एक दूसरे को खुलेदिल से माफ़ कर दें और ईद के त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाए। ईद का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद शहरों और देहातों में घरों के बाहर कन्दीलें बांस से बनायी जाती हैं और उसे रोशन करने के लिए मिटटी का तेल प्रयोग किया जाता है। इंडोनेशिया में यह कन्दील प्लेटयाया पन्जोत कहलाती है और मलायी भाषा में इसे लेम्पो क्लाक कहते हैं। ईद के अवसर पर स्पेशल खाने, उदाहरणार्थ डोडोल, कोकीज रेन्डिग और सबसे ख़ास सौगात किटूपाट होती है जिसमें चावलों को नारियल के पत्तों में रखकर पकाया जाता है यहां लोग एक दूसरे से मिलते समय मोहन माफ ला हरदान बातिन या माफ ज़ाहिरदान बातिन भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ईद मिलने वाले व्यक्ति से अगर कोई ग़लती हो गयी हो जिससे मिलने वाले को कोई दिली या जिस्मानी पीड़ा पहुंची हो तो उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि लोगों का ख़्याल है रमज़ान में सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इंसान पाक साफ हो जाता है।

इंडोनेशिया और मलेशिया में रहने वाले मुसलमान ईद के दिन अपना परम्परागत लिबास पहनने को वरीयता देते हैं। इंडोनेशिया में पुरूषों के लिबास को बाजू कोको कहा जाता है, यह सफेद रंग का छोटा या लम्बा चोगा होता है जिस पर परम्परागत कढ़ाई छपाई होती है जबकि पश्चिमी लिबास पहनने पर भी प्रतिबंध नहीं है। इंडोनेशियन औरतें ईद के दिन एक ढीले ढाले ब्लाउज़ के साथ लान्ग स्कर्ट पहनती हैं। इस पूरे लिबास पर भी एम्ब्रायडरी होती है और चेहरे को छुपाने के लिए जलबाब या हिजाब लगाया जाता है। इस परम्परागत लिबास को बाजू करंग या बाजू कबाया कहते हैं। मलेशिया में रहने वाले ग़ैर मुस्लिम भी मुसलमानों के जज़्बातों के सम्मान में यही परम्परागत लिबास पहनते हैं। दूसरे देशों की तरह इंडोनेशिया में भी बच्चों का जोश व जज़्बा देखने लायक़ होता है उन्हें अपने बड़ों की तरफ से लिफाफे में ईदी मिलती है जिसे खर्च करने के लिए वह अपने मित्रों के साथ ओपन हाउस जाते हैं, मलेशिया में बच्चों को मिलने वाली ईदी को दोतराया कहते हैं।

तुर्की:- इंडोनेशिया और तुर्की में मनायी जाने वाली ईदुल फितर में बहुत अंतर है। इंडोनेशिया में नमाज़ ईद के लिए औरतें मर्द दोनों ही जा सकते हैं जबकि तुर्की में सिर्फ आदमी ही ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और औरतें घरों ही में रहती हैं। तुर्की में पुरानी परम्परा है कि जब मर्द नमाज़ पढ़कर घर आते हैं तो बीवी अपने शौहर के हाथ के पीछे वाले भाग पर बोसा (चूमना) लेती है। और बच्चे मां और बाप दोनों के हाथ पर बोसा देते हैं। बच्चे इन बुजुर्गों के हाथ पर बौसा देते हैं जो इनके घर पर बतौर मेहमान आते हैं तुर्की में ईद के रोज़ कुछ ख़ास डिशेज (पकवान) तैयार नहीं की जाती बल्कि मामूल वाला खाना बनता है। तुर्की में ईद के पहले दिन हर घर के बच्चे बारी बारी सारे पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खुलने पर पड़ौसी को 'ऐ बैरामलट या मुबारक ओ सलून कहते हैं, फिर पड़ौसी उन्हें केन्डीज या चॉकलेट देते हैं। अगर बच्चे को एक टाफी भी मिल जाए तो उसकी खुशी देखने के लायक़ होती है इस कार्य का उद्देश्य जज़्बए खैर सगाली है फिर बच्चों को घर के बड़ों से परम्परागत ईदी मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि बुजुर्ग नौजवान को भी ईदी देते हैं जो खुद कमातें हों या शादीशुदा हों। तुर्की में भी ईद के लिए सब से पहले कपड़ों, केन्डीज, चॉकलेट की खरीदारी की जाती है। ईद के अवसर पर अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाना भी आवश्यक कार्य है।

सऊदी अरब:- सऊदी अरब में ईदुल फित्र मनाने का तरीक़ा दूसरे इस्लामी देशों के मुक़ाबले अलग है। यहां ईदुल फितर अत्याधिक शान शौक़त के साथ मनाई जाती है। लोग घरों को नए सिरे से सजाना, संवारना करते हैं और मित्रों रिश्तेदारों की खातिरदारी के लिए तरह तरह के खाने भी तैयार किए जाते हैं। पूरे देश में एक रंग रूप, भाईचारे का वातावरण दिखायी देता है। ईद को मनाने का तरीक़ा राज्य या क्षेत्र के लिहाज़ से अलग हो सकता है, मगर एक चीज़ जो उन सबको एक लड़ी में पिरों कर रखती है वह मेहमान नवाज़ी और सखावत है जो पूरे देश में एक जैसी होती है। ईद के अवसर पर सऊदी लोग अत्याधिक सखावत और फराखदिली का प्रदर्शन करते नज़र आते हैं और अजनबियों से भी अत्याधिक नम्रता से मिलते हैं। सऊदी अरब में लोग परिवार के प्रमुख या बुजुर्ग के घर जमा होकर निकट में ही मैदान में नमाज ईद अदा करते हैं और नमाज़ के बाद खाना खाया जाता है, यूँ खानदान ही में एक छोटा सा आयोजन हो जाता है। इस अवसर पर बच्चों में तोहफें भी बांटे जाते हैं। जिनकी पैकिंग अत्याधिक खूबसूरत होती है। इन पैकेटस में टाफियां और खिलौने होते हैं। बच्चो को अजनबी लोगों की तरफ से तोहफें भी दिए जाते हैं सऊदी अरब में ईद के अवसर पर लोग इतनी ख़ामोशी से दूसरों की मदद करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि इनकी मदद किसने की। इसके लिए वह यह तरीका अपनाते हैं कि दाल चावल, गेहूं और नए कपड़े खरीदने के बाद उन्हें ज़रूरतमंदों के घरों के बाहर रखवा देते हैं, इसी तरह इनकी मदद भी हो जाती है और इन्हें किसी का अहसानमंद भी नहीं होना पड़ता। मध्य शहर अल कासिम में एक रिवायत यह भी है कि ईद की सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सारे पड़ौसी अपने घरों से बाहर दरियां या कालीन बिछाते

ख़ास ख़बरें

मैक्रों फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति

पेरिस : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दोबारा देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को कड़ी टक्कर दी और उनकी इस जीत के साथ ही फ्रांस के सहयोगियों ने राहत की सांस ली है कि यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपने रुख़ में कोई बदलाव नहीं करेगा तो यूरोपीय संघ और नाटो के प्रयासों को समर्थन जारी रखेगा।

लंदन में 4 लोगों की चाकू घोंपकर हत्या

लंदन : दक्षिण लंदन में एक घर में 4 लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। इस बाबत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मैट्रोपोलिटन पुलिस बल ने कहा कि 24-25 अप्रैल की मध्य रात्रि को पुलिस को सूचित किया गया जिसके बाद अधिकारी बरमोंडे क्षेत्र पहुंचे। घर में उन्हें 3 महिलाएं और एक पुरुष मिला जिनको चाकू घोंपा गया था। चारों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

16 यू-टयूब चैनल बैन

नई दिल्ली : देश में प्रोपेगंडा फैलाने वाले 6 पाकिस्तानी यू-टयूब चैनलों को भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत से चलने वाले 10 अन्य यू-टयूब चैनलों पर यह कार्रवाई की गई है। इन सभी चैनलों की कुल मिलाकर 68 करोड़ के करीब व्यूअरशिप थी। सरकार का मानना है कि इन चैनलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। इन चैनलों से लोगों में गलत मैसेज जा रहा था और इनमें से कई चैनल झूठी ख़बरें परोस रहे थे। इसलिए इनको प्रतिबंधित किया गया है।

कई राज्यों मे गहरा सकता है बिजली संकट

जालंधर : पिछले कुछ सप्ताह से पंजाब सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है जबकि केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें समस्या के समाधान के लिए क़दम उठा रही हैं, यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है। पिछले वर्ष भी कई राज्यों ने ताप विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त कोयले की आपूर्ति पर चिंता जताई थी। यह मांग का सटीक अनुमान लगाने और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को प्रबंधित करने में एक प्रणालीगत अक्षमता को दर्शाता है।

ईदुल फित्र ईनाम का दिन

जब तक ये पंक्तियाँ आप तक पहुंचेगी इन्शाअल्लाह आप सभी ईद मनाने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे क्योंकि ईद हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। पिछले लगभग दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से हमने ईद की नमाज़ कहीं पढ़ी और कहीं नहीं पढ़ी गई, और सरकार की बंदीशें को अमल में लाते हुए हमने ईद मनाई। इस बार इन्शाअल्लाह हम सब ईद की नमाज़ पूरे शौक़ ज़ौक से ईदगाह में पढ़ेंगे। ईदुल फित्र सिर्फ त्यौहार ही नहीं एक तरह से अल्लाह की तरफ से ईनआम का भी दिन है, ये इनआम उन रोज़ेदारों के खास है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़ो बिला नाग़ा रखे। ईद का दिन खुशी व मसर्रत का दिन है क्योंकि इस दिन सदक़ा फितर अदा किया जाता है लिहाज़ा इसका नाम ईदुल फित्र हो गया। दुनिया में शुरू से त्योहार मनाने की परपंरा रही है लेकिन कौमें और रस्मों के अनुसार खुशी का य दिन मनाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईद मनायी जाती थी लोग शहर से दूर जाकर शुक्र व खुशी का इज़हार करते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी क़ौम बनी इस्राईल को अल्लाह तआला ने फिरऔन के जुल्म व सितम से निजात अता की, इसकी खुशी में बनी इस्राईल के लोग ईद मनाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर इनकी कौम के लिए खुदाए तआला ने मायदा (नेमतों के दस्तरख्वान) का नुजूल फरमाया और इसकी यादगार के तौर पर ईद मनायी जाती रही। पैग़म्बर इस्लाम हज़० मौहम्मद सल्ल० मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां पहले से स्थानीय आबादी मेहरजान और नवरोज़ के नाम से दो त्यौहार मनाती थीं। आप (सल्ल०) ने इन त्यौहारों के बजाय ईदुल फित्र और ईदुल अज़्हा के त्यौहार मनाने का हुक्म दिया तब से मुसलमान सिर्फ इन दो दिनों मे ही ईद मनाते हैं। इसके अलावा नहीं इनमें से भी ईदुल फित्र रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे होने के बाद परवरदिगार आलम के प्रति शुक्र के इज़हार के तौर पर मनायी जाती है। इस दिन रोज़ेदार को ईनाम से भी नवाज़ा जाता है। इस ईद को मनाने का हक़ इन्हीं लोगों को है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अहतमाम के साथ रखें और दूसरी इबादतों में अधिक से अधिक जुटे रहे यानि अपने दिन रात इसी तरह गुज़ारे जिस तरह अल्लाह तआला और उसके रसूले पाक सल्ल० ने हुक्म दिया है यानि ईदुल फित्र की असली हैसिअत रमज़ान मुबारक में की गयी नेकियों पर अल्लाह तआला की तरफ से ईनाम के दिन की है यानि ईद की हक़ीक़ी खुशियां उन लोगों के लिए विशेष हैं जिन्होंने इस माह मुबारक में अपना अधिकतर समय इबादत और मालिक दोजहां की खुशनूदी प्राप्त करने में खर्च किया इनके लिए ईदुलफित्र ईनाम का दिन है।

अल्लाह सुब्हाना व तआला को रमज़ान में अपने बन्दों का भूखा प्यासा रहना मतलूब नहीं बल्कि रोज़े आत्म संयम, और रूह को जज़्बए ईमानी से भरने का एक माध्यम है जिस तरह कुर्बानी के बारे में फरमाया गया कि हक़ जल्ला शानहू को जानवर की हडिडया गोश्त और खून नहीं चाहिए बल्कि तक़्वा और परहेज़गारी उद्देश्य है। इसी तरह रोज़ेदार को भी भूखा रखना और मानसिक इच्छाओं पर एक माह क़ाबू पाना मक़्सूद नहीं है बल्कि असल चीज़ जो मतलूब व मक़्सूद है वह एक मोमिन की रूहानी तरबियत है। रमज़ान के रोज़े जहां इंसान में अमल सालेहा (सदव्यवहार) का जज़्बा पैदा करते हैं वहीं ग़रीबों, रिश्तेदारों और दूसरे असहायों से ज़क़ात, सदक़ा और फितरा के माध्यम से हुस्ने सुलूक की भी शिक्षा देते हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोगों से जो हाथ फैलाने में शर्म महसूस करते हैं लेकिन यह सभी काम नाम ऊंचा करने या दिखावा करने के जज़्बे से नहीं होना चाहिए क्योंकि दिखावे की इबादतें अल्लाह तआला की जानित में क़बूल नहीं, ऐसी इबादतें करने वाले के मुंह पर फेंक दी जाएंगी इसलिए ज़रूरत इसकी है कि मुसलमान हर अच्छा कार्य अंजाम देते समय अपनी नीयत ठीक रखें और इबादतों के साथ अपने मामलों कार्यों में भी सुधार कर लें, जहां अपनी ज़बान व बयान पर क़ाबू पाएं वहीं आपसी एकता एकजुटता का वातावरण पैदा करने पर भी ध्यान दें, तभी एक अच्छा समाज अस्तित्व में आएगा और हमारा अमल दूसरों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करने का माध्यम बनेगा।

अमीर सिपाही

बादल सुल्तानपुरी

उसी राहबर पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है
जो कभी अमीरे सिपाह है तो कभी मुजाहिदे आम है

कोई आज तक न समझ सका जो मुस्तफा का मक़ाम है
कभी बोरिये पे क़याम है कभी अंबिया का इमाम है

कभी ताजदारे जहान है, कभी ग़मगुसारे अनाम है
कभी बकरियों का है पासबां, कभी मेहरबाने गुलाम है

कभी फ़ाक़ा कश कभी मेज़बा, कभी सर पे ताजे शहंशही
कभी सफ़ शिकन कभी बुत शिकन, कभी दर्दमंदे अवाम है

कभी कह दिया कि अना बशर, कभी आसमां पे है जल्वागर
कभी उम्मे हानी के घर, कभी सरे अर्श महवे ख़िराम है

हुआ चुप तो उम्मी ही बन गया, खुले लब तो उक़्दा कुशा हुआ
कोई उसके बारे में क्या कहे कि वो ख़ास है कि वो आम है

यहां बादल आज भी ऐ नबी, है सुकूने दिल से नाआशना
बड़ा इज्तिराब है दर्द है, बड़ा मुज्तरिब ये गुलाम है

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बकरह नं० 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और जब हमने फरिश्तों को आदेश दिया कि आदम को सज्दा करो तो शैतान के अतिरिक्त सब सज्दे में गिर पड़े।

जब हज़रत आदम अलै० का उत्तराधिकारी होना माना जा चुका तो फरिश्तों के साथ जिनों को भी आदम की ओर सज्दा करने को कहा गया। जिस प्रकार बादशाह अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, फिर पदाधिकारियों को उपहार आदि देने को कहते हैं ताकि किसी को अवज्ञाकारिता की हिम्मत न रहे। अत: सबने सज्दा किया, शैतान के अतिरिक्त जो कि जिनों में से था और फरिश्तों के साथ बहुत घुला मिला रहता था। उसकी अवज्ञाकारिता का कारण यह हुआ कि जिन कई हजार साल से ज़मीन में राज्य करते थे और आसमान पर भी आते जाते थे जब उनका उपद्रव और रक्तपात बढ़ा तो फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश से कुछ को क़त्ल किया और कुछ को जंगल पहाड़ों और टापुओं में भगा दिया। शैतान उनमें बड़ा विद्वान और उपासक था। उसने जिनों के उपद्रव से अपना अलगाव प्रदर्शित किया। फरिश्तों की सिफारिश से वह बच गया और उन्हीं में रहने लगा और इस लालच में कि ज़मीन पर तमाम जिनो के स्थान पर केवल उसको उत्तराधिकारी बनाया जाये। दिन-रात उपासना में लगा रहा और ज़मीन में अल्लाह का उत्तराधिकारी बनने का विचार मन में बिठाए रहा। जब आदम अलै० की ख़िलाफ़त (उत्तराधिकारिता) का आदेश अल्लाह की ओर से हुआ तो उसको अपनी दिखावे की उपासना के नष्ट होने का अफसोस हुआ और ईर्ष्या के कारण सज्दा नहीं किया और धिक्कारा गया।

उसने न माना और घमंड किया और वह इनकारियों में से था।

अर्थात् अल्लाह की जानकारी में पहले ही इनकारी था यद्यपि दूसरों के सामने उसका इनकार अब खुल गया या यूं कहो कि अब इनकारी हो गया। इस कारण कि अल्लाह के आदेश का घमंड से इंकार किया और अल्लाह के आदेश को वस्तुतत्व के विरुद्ध समझा और अपने अपमान का कारण समझा। यही नहीं कि सज्दा नहीं किया।

और हमने कहा ऐ आदम तू और तेरी पत्नी जन्नत में रहा करो और जो चाहो जहां कहीं से चाहो उसमें खाओ और इस वृक्ष के पास मत जाना नहीं तो तुम भी ज़ालिम हो जाओगे।

प्रसिद्ध है कि वह पेड़ गेहूं का था और कुछ लोगों ने अंगूर या इंजीर आदि का बताया।

फिर शैतान ने उनको उस स्थान से हिला दिया फिर उनको उस सम्मान और सुख के स्थान से निकाल दिया जिसमें वे दोनों थे।

कहते हैं कि हज़० आदम और हव्वा जन्नत में रहने लगे और शैतान को उसके सम्मान के स्थान से निकाल दिया तो शैतान की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गयी अन्त में शैतान, मोर और सांप से मिलकर जन्नत में गया और बीबी हव्वा को बहकाया, जिससे उन्होंने उस पेड़ से खा दिया और हज़ आदम अलै० को भी खिलाया और उनको विश्वास दिला दिया था कि उसके खाने से अल्लाह के सदैव के लिए प्रिय बन जाओगे और अल्लाह ने जो मनाही की थी उसके झूठे अर्थ घड़कर बता दिये। यह घटना आगे सूरा नं० 7 रुकू नं० 2 में विस्तार रूप से आयेगी।

और हमने कहा तुम सब उतरो तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होगे।

इस भूल की सज़ा में हज़रत आदम और हव्वा और जो औलाद पैदा होने वाली थी सबकी ओर यह आदेश हुआ कि सब ज़मीन पर जाकर रहो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे, जिसके करण कष्ट उठाओगे। यहां से जाओ जन्नत पाप और दुश्मनी करने का स्थान नहीं। इन बातों के अनुकूल दुनिया है जो तुम्हारी परीक्षा के लिए बनायी गई है।

धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन तैयार करने की आवश्यकता

धार्मिक संस्थान और जितने भी जरूरत के मामलों हैं उन सब धार्मिक कार्यों के प्रचार के लिए उचित सिद्धांत के साथ देश-विदेश फिरते हुए कोशिश करना धार्म की ज़मीन तैयार करने जैसा है और अन्य जितने भी मामलों हैं वह इस ज़मीन के ऊपर बाग़ात की परवरिश करने जैसा है, बाग़ हजारों प्रकार के होते हैं, कोई खजूरों का है, कोई अनारों का है, कोई सेबों का, किसी में केले हैं और कोई फुलवारियों का बाग है, बाग हज़ारों प्रकार के हो सकते हैं लेकिन कोई बाग दो चीजों के अंदर पूरी पूरी कोशिश करने के बिना नहीं हो सकता। पहली ज़मीन का बराबर और सटीक होना, ज़मीन बराबर करने में प्रयास के बिना या ज़मीन में कोशिश करके खुद उन बागों का स्थायी पोषण किये बिना कोई बाग परवरिश नहीं पा सकता। इसलिये दीन में तबलीगी कामों की कोशिश यह तो धर्म की ज़मीन है और सब संस्थानएं बाग हैं, अब तक धर्म की ज़मीन ऐसी बीहड़ और हर तरह के उत्पादन से इतनी अनुचित हो रहा है कि कोई बाग उस पर नहीं लगता। (मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी तबलीगी दावत)

सीबीआई के शिकंजे में पश्चिमी बंगाल ममता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दायर हो रहे मामले

पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की ना-नुकुर और उनकी पार्टी के बगावती तेवर के बावजूद भ्रष्टाचार और संज्ञेय अपराध के मामले धड़ाधड़ सीबीआई में दर्ज हो रहे हैं। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के बाद तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई। सीबीआई के पास जितने मामले इस दौरान दर्ज हुए हैं, वे सभी बंगाल की पुलिस से छीन कर हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपे हैं। हालत यह है कि तीन सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट के निर्देश पर 6 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं।

विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर बंगाल में हिंसा हुई। रेप और हत्याओं के मामलों का विपक्ष ने मुद्दा उठाया। राज्य सरकार इससे इंकार करती रही। आख़िरकार हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इसकी जांच राज्य सरकार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सीबीआई को सौंप दी।

पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं लगातार उजागर होती रही हैं। भ्रष्टाचार के भी कई मामले सामने आए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसे मामलों की जांच पुलिस के बजाय सीबीआई करने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह नागवार लगता है। वह लगातार सीबीआई जांच की मुख़ालफत करती रही हैं।

उसके बाद हिंसा के तकरीबन साढ़े चार दर्जन मामलों में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। बीते दिनों यानि मार्च में रामपुरहाट में नौ हत्याएं हुईं। पहले एक जनप्रतिपिधि भादू शेख़ की हत्या हुई। उसके बाद एक ही दिन घरों बंद कर आठ लोगों को ज़िन्दा जला दिया गया। हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों को सीबीआई को सौंप दिया। झालदा में कांग्रेस से जुड़े एक काउंसलर की हत्या हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस से छीनकर वह मामला भी जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। पशु तस्करी का मामला भी सीबीआई के पास है। इस मामले के एक आरोपी टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने तलब किया तो वह बीमार होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए। एसएसजी नियुक्ति घोटाले में टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्ती समेत कई लोग सीबीआई के शिकंजे में हैं। रेप के बढ़ते मामलों पर भी हाईकोर्ट का रुख़ सख़्त है। कहीं ये मामले भी सीबीआई को न सौंप दिए जाएं। अगर यही हालत रही तो बंगाल की पुलिस बेरोज़गार हो जाएगी और सीबीआई को बंगाल के लिए अलग विंग न बनानी पड़े।

पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं लगातार उजागर होती रही हैं। भ्रष्टाचार के भी कई मामले सामने आए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसे मामलों की जांच पुलिस के बजाय सीबीआई करने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह नागवार लगता है। वह लगातार सीबीआई जांच की मुख़ालफत करती रही हैं। राज्य सरकार की इजाज़त के बग़ैर सीबीआई जांच के ख़िलाफ़ वह सुप्रीम कोर्ट तक गई। ग़ैर भाजपा शासित राज्यों को विश्वास में लिया। सात राज्यों ने बिना इजाज़त सीबीआई को अपने-अपने राज्यों में जांच से मना भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी।

इधर हाईकोर्ट लगातार आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच बंगाल पुलिस से वापस लेकर सीबीआई को सौंप रहा है। हार कर ममता ने सीबीआई समेत तमाम केन्द्रीय एजेंसियों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र समेत ग़ैर भाजपा शासित पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केन्द्रीय जांच एजेंसियों पर राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एकजुटता की अपील की है। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थकों के ख़िलाफ़ कहीं सीबीआई, आईटी तो कहीं ईडी की जांच चल रही है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन और सारदा चिटफंड घोटाले की जांच पहले से ही हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता तो इन मामलों में जेल तक जा चुके हैं। ममता की बौखलाहट की असल वजह यही है।

बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के मारे जाने, महिलाओं से दुष्कर्म किए जाने, वीरभूम जिले के रामपुरहाट में आठ लोगों को ज़िन्दा जला दिए जाने, रामपुरहाट में ही भादू शेख़ की हत्या, एसएससी नियुक्ति घोटाला समेत दर्जनों मामलों की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंप दी है। कोयला और पशु तस्करी के मामलों की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। वामदल तो हावड़ा में हुई एक छात्र की मौत की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नदिया जिले में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामलों पर भी घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट में यह मामला भी पहुंच गया है। इसी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया हैं ममता बनर्जी इस मामले में हास्यास्पद बयान देकर फंस गई। उन्होंने कहा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है हम यूपी की तरह लव जिहाद इसे नहीं ठहरा सकते।

ममता बनर्जी ने केन्द्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को एकतरफा पीड़क कार्रवाई क़रार देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिख एकजुट होकर आवाज़ उठाने की मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविास अघाड़ी की सरकार हे। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के 14 नेताओं के ख़िलाफ़ जांच चल रही है। इनमें प्रमुख नौ लोगों की सूचि एक अख़बार ने पिछले दिनों प्रकाशित की थी। इनमें अनिल देशमुख के ख़िलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी की जांच चल रही है। अनिल परब पर ईडी, सीबीआई और आईटी ने शिकंजा कसा है।

वर्षा रावत और संजय राउत के ख़िलाफ़ ईडी और आईटी की जांच चल रही है। अजित पवार के ख़िलाफ़ भी ईडी और आईटी की जांच चल रही हैं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के ख़िलाफ़ भी ईडी की जांच जारी है। अशोक चव्हाण के खिलाफ़ ईडी, सीबीआई और आईटी की जांच चल रही है। हसन मुशरिफ और नवाब मलिक भी केन्द्रीय जांच एजेंसियों के लपेटे में हैं। ममता बनर्जी के मंत्री, नेता या उनकी पार्टी के समर्थक जिस तरह भ्रष्टाचार या दूसरे संज्ञेय आपराधिक मामलों में केन्द्रीय जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, उससे उन्हें महाविकास अघाड़ी की सरकार से समर्थन की उम्मीद स्वाभाविक है। ❑❑

बिहार- तेजस्वी की सियासी गुगली

हाल ही में सम्पन्न बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की सभी 24 सीटों के चुनाव में सत्तारुढ़ भाजपा-जदयू गठबंधन भले 13 सीटों पर कब्ज़ा जमाने में सफल रहा, लेकिन गरमागरम सियासी चर्चा तो राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नए सामाजिक राजनीतिक प्रयोग की है। इन चुनावों में भाजपा को सात, जदयू को पांच, पशुपति कुमार पारस ग्रुप के रालोजपा को एक सीट पर जीत मिली जबकि एनडीए के पास पहले इन 24 में से 21 सीटें थीं। विपक्षी राजद, जिसके पास इनमें से सिर्फ दो सीटें थीं, को इस बार छह और कांग्रेस को एक सीट पर विजय मिली। चार सीटों में निर्दलीय ने जीत हासिल की। इस बार तेजस्वी ने पांच भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें तीन विजयी हुए। कुल मिलाकर, राजद ने कुल 24 में 10 स्वर्ण उम्मीदवार उतारे, जिनमें पांच भूमिहारों के अलावा चार राजपूत और एक ब्राह्मण था।

राजद के इतिहास में यह पहला अवसर था जब पार्टी ने 40 प्रतिशत सीटों पर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को खड़ा किया था। सियासी गलियारों में इसे तेजस्वी का नया 'भूमाय' (भूमिहार-मुस्लिम-यादव) समीकरण कहा जा रहा है।

ग़ौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार में संयुक्त रूप से लगभग 30 प्रतिशत आबादी वाले मुस्लिम-यादव (माय) समीकरण के बल पर पन्द्रह सालों तक अपनी सत्ता चलाई थी, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए माय समीकरण असरदार साबित नहीं हुआ। इसका एक प्रमुख कारण राज्य में स्वर्ण जातियों का जदयू/ भाजपा गठबंधन का भरपूर समर्थन भी रहा है। इसलिए, तेजस्वी अब सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात कर कह रहे हैं और सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव में उन्होंने 40 प्रतिशत सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया।

पिछले तीस सालों से भूमिहार लालू के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं और एनडीए की जीत में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है, तो क्या भूमिहार वोटर भविष्य में राजद को समर्थन दे सकते हैं? यह बड़ा प्रश्न है। इस चुनाव में राजद के छह प्रत्याशियों ने सफलता पाई, जिनमें तीन भूमिहारों के अलावा एक राजपूत उम्मीदवार भी शामिल है। यह भी दिलचस्प है कि राजद में माय समीकरण को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया और नौ यादव और एक मुस्लिम को भी टिकट दिया, लेकिन उनमें जीत सिर्फ एक यादव उम्मीदवार की ही हुई। सियासी जानकार इसे तेजस्वी की नया राजनीतिक ताना-बाना बुनने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, हालांकि एनडीए के नेता इन परिणामों का अगले लोकसभा या विधान सभा चुनाव पर किसी तरह के असर की संभावना से इंकार कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि लालू का सवर्णों के ख़िलाफ़ ''भूरा बाल साफ करो'' का नारा भले ही पुराना पड़ गया हो पर लोग उसे भूले नहीं हैं। उनका कहना हे कि जिनका राजद से कोई निजी स्वार्स्थ सध रहा हो, वे ही उस ओर जाएंगे, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों।

राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि पहले ऊपरी सदन में राजद एमएलसी की संख्या चार थी और अब बढ़कर छह हो गई। ज़ाहिर है, वोट प्रतिशत भी बढ़ा और संख्या भी। वे आगे कहते हैं कि आधुनिक राजनीति में प्रयोग हमेशा होते रहते हैं। विशेषकर गहरी जाति फीजिंग वाले राज्य बिहार में कई उपजातियां भी हैं। ऐसे में कास्ट इक्वेशन और एलायंस से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता।

जटिल जातिगत बुनावट वाले राज्य बिहार में राजद के पार्टी की राजनीतिक परंपरा से अलग हटकर सवर्ण जातियों में विशेषकर भूमिहारों को अधिक टिकट देने से अगले संसदीय चुनाव के समीकरण पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तेजस्वी कहते हैं, ''मैं नया हूं और नया बिहार बनाना चाहता हूं, जिसमें जात पांत बहुत मायने नहीं रखती।'' लेकिन समाज और राजनीति में गहरी रूचि रखने वाले जानकार इसे राजनीतिक स्टंट से अधिक कुछ नहीं मानते। उनका मानना है कि राजपूतों के राजद से बिदकने के कारण तेजस्वी ने भूमिहार कार्ड खेला है। एम-वाय तो पहले से ही था, अब जुगाड़ में 'भू' को जोड़ने के लिए नया फार्मूला टिकट देकर फिट करने की जुगत में लग गए हैं। बहरहार, तेजस्वी के नए प्रयोग का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, यह तो अगले चुनाव में ही पता चलेगा। ❑❑

चहल गड़े मुर्दे उखाड़ रहे कुछ हासिल नहीं होगा श्रीसंत

पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ एस. श्रीसंत ने 2007 टी-20 विश्व कप में जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज़्यादा उनका कैरियर विवादों में रहा। आईपीएल में हरभजन सिंह से थप्पड़ खाने के बाद जो सहानुभूति मिली, उसे उन्होंने फिक्सिंग के आरोप लगने से गंवा दिया। उन पर प्रतिबंध लगा और मैदान पर लाख कोशिश करने पर भी सफल वापसी नहीं कर सके। श्रीसंत अब नए सिरे से अपनी ज़िन्दगी की शुरूआत करना चाहते हैं, पेश है श्रीसंत से हुई एक वार्तालाप के प्रमुख अंश:-

प्रश्न:-आईपीएल नीलामी में नहीं बिकने के पीछे क्या कारण रहा?

उत्तर:- पिछले दो सालों से मैं आईपीएल में वापसी करना चाह रहा था, जो हो नहीं सका। शायद इसके पीछे मेरी बढ़ती आयु हैं मुझे ख़ुशी इस बात की है कि फ्रेंचाइजियों ने युवा क्रिकेटरों को ज़्यादा मौक़ा दिया है और वे बढ़िया प्रदर्शन कर भी रहे है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत हैं।

प्रश्न:- आईपीएल से आपने क्या हासिल किया और क्या खोया?

उत्तर:- पंजाब की ओर से खेलते हुए 2008 में आख़िरी समय तक पर्पल कैप मेरे पास रहा। अन्तिम समय में शेन वार्न और सोहेल तनवीर मुझसे आगे निकल गए। शेन वार्न जैसे दिग्गजों के साथ खेलकर काफी कुछ सिखने को मिला। सही समय पर समर्थन नहीं मिलने से मुझे काफी नुकसान हुआ।

प्रश्न:- आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगने के बाद आपको सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट मिला?

उत्तर:- मुझे मेरे परिवार, आदित्य वर्मा सर और खासकर नैंजी (पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी) से काफी सपोर्ट मिला। मैंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन नैंजी और अपनों ने मुझे एक मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनों ने मुझे मुसीबत के समय टूटने से बचाया।

प्रश्न:- क्रिकेट से आपने अचानक संन्यास क्यों लिया.?

उत्तर:- केरल की ओर से रणजी में मैं 130-140 की स्पीड से गेंद डाल रहा था। मध्य प्रदेश के खिलाफ़ मुक़ाबला हारने से मेरी टीम नाकआउट में नहीं पहुंच सकी। इसके बाद मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। में अभी तीन साल तक एक स्थानीय लीग खेलता रहूंगा। मुझे बीसीसीआई से उम्मीद है कि उनकी देखरेख में भारतीय युवा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाएंगे।

प्रश्न:- इस वर्ष होने वाले टी-20 विश्व कप में टीम इंडिया में कौन से गेंदबाज़ शामिल हो सकते हैं..?

उत्तर:- कुलदीप यादव ने शानदार वापसी की है। युजवेन्द्रा सिंह चहल और मोहम्मद शमी बढ़िया कर रहे हैं। अक्तूबर में आस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए शमी तो टीम में रहेंगे, लेकिन कुलदीप या चहल से किसी एक को रहना चाहिए।

प्रश्न:- रोहित, विराट और राहुल के फ्लॉप होने का असर टी-20 विश्व कप पर पड़ेगा.?

उत्तर:- तीनों लीजेंड है और मुझे विश्वास है कि वे बढ़िया प्रदर्शन कर भारत को विश्व कप कप ख़िताप दिलाएंगे।

प्रश्न:- चहल ने 2011 में चैम्पियंस लीग टी-20 के दौरान खुद को बालकनी से लटकाए जाने का आरोप एक क्रिकेटर पर लगाया है। आप क्या कहेंगे..?

उत्तर:- 11 वर्ष बाद इस तरह रहस्योद्घाटन कर गड़े मुर्दे उखाड़ने से चहल को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्हें उसी समय इस घटना के बारे में जानकारी देना चाहिए था मुझे लग रहा है कि उन्होंने में यह सब बोला है।

प्रश्न:- क्रिकेट में आपका सबसे यादगार पल और भूल जाने वाला क्षण?

बाक़ी पेज 11 पर

हार से आहत जो रूट ने इंग्लैंड की टैस्ट कप्तानी छोड़ी

एशेज सहित पिछली कुछ श्रृंखलाओं में हार से आहत जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट कप्तान पद से त्यागपत्र दे दिया। इससे उनके पांच वर्ष के चुनौतियों से भरे कार्यकाल का भी अंत हो गया। रूट ने कहा, 'मुझे अपने देश की अगुआई करना पसंद है लेकिन हाल में मुझे अहसास हुआ कि इससे मुझ पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में 31 वर्षीय रूट के नाम पर सर्वाधिक मैचों में जीत का रिकॉर्ड हैं उनकी अगुआई में इंग्लैंड ने 27 मैच जीते हैं जो माइकल वॉन से एक अधिक व एलिस्टेयर कुक और एंड्रयू स्ट्रॉस से तीन अधिक हैं।

एक बल्लेबाज़ के रूप में रूट की टीम की जगह सुनिश्चित है क्योंकि 2021 के बाद से उन्होंने आठ शतक बनाए हैं और वह दुनिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में शामिल हैं। लेकिन पिछले 17 टैस्ट मैचों में इंग्लैंड केवल एक मैच में ही जीत दर्ज कर पाया है जो 1980 के बाद टीम का सबसे ख़राब प्रदर्शन है। इससे रूट की कप्तानी पर प्रश्न उठाने लगे थे। आस्ट्रेलिया में एशेज श्रृंखला में 0-4 से करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड पिछले माह वेस्ट इंडीज से टेस्ट श्रृंखला में 0-1 से हार गया था। यह उसकी टैस्ट श्रृंखलाओं में लगातार चौथी हार है। यदि भारत जुलाई पिछले वर्ष की श्रृंखला के एकमात्र बचे टैस्ट में जुलाई में उसे हरा देता है तो यह उसकी लगातार पांचवीं हार हो जाएगी।

रूट ने कहा 'यह मेरे कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण फैसला रहा है, लेकिन अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ इस बारे में चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि अब कप्तानी छोड़ने का सही समय है।

काली मिर्च के अनेक है फायदे

''काली मिर्च'' हमारे पारंपरिक मसालों की श्रेणी में आती है। इसके अनेक फायदे हैं, इस इस्तेमाल अनेक आर्युवैदिक दवाइयों और काढ़ा बनाने में किया जाता है, खाने में इस्तेमाल के साथ-साथ इसके और अन्य फायदे हैं। काली मिर्च किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। काली मिर्च हर घर की ज़रूरत और रसोई की शान है। दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसकी खेती की जाती है। चरपरा स्वाद के लिए काली मिर्च को सलाद पर या कटे फलों पर डालकर खाने का अपना मज़ा है। काली मिर्च रसाईघर में मसालों के रूप में और रसोईघर के बाहर कई बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। आईये जानते हैं काली मिर्च के कुछ घरेलू नुस्खे जो बहुत उपयोगी है।

भूख को बढ़ाने में, पेट के कीड़ों को मारने में, कफ को दूर करने में काली मिर्च अति उत्तम है।

पेट में अफारा होने पर काली मिर्च के सेवन से लाभ पहुंचता है। काली मिर्च का आकार चाहे छोटा है परन्तु गुणों से भरपूर होती है।

पिसी हुई काली मिर्च को आधा चम्मच मक्खन और घी के साथ मिलाकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है।

काली मिर्च के दानों को कुछ मोटा कूट थोड़ी सी हल्दी और दही मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। इसे माथे पर लगाने से सिरदर्द में आराम मिलता है।

काली मिर्च के दानों को पत्थर पर थोडा सा पानी डालकर घिसें। इस लेप को अनामिका अंगुली से शरीर पर उठती हुई फुंसी पर लगाने से फुंसी बैठ जायेगी।

अपना हाज़मा ठीक रखने के लिए काली मिर्च, सेंधा नमक, पीपल और ज़ीरे को बराबर मात्रा में पीस कर मिला लें। भोजन के बाद इसे आधे चम्मच की मात्रा में पानी के साथ फांकें। दस बारह दिन तक सेवन करने से पेट का हाज़मा ठीक हो जाता है।

काली मिर्च का चूर्ण आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर चाटने से अंदर जमा कफ बाहर निकलता है और सांस लेने में राहत मिलती है।

काली मिर्च, 15 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम जीरा पीस कर मिला लें, एक चम्मच शाम को पानी के साथ सेवन करने से बवासीर के रोगियों को लाभ पहुंचता है।

काली मिर्च, मुलहठी और मिश्री के चूर्ण का नियमित सेवन करने से आवाज़ में सुरीलापन लाया जा सकता है।

भुनी हुई फिटकरी और काली मिर्च पीसकर मस्सों पर लगाने से मस्से मिट जाते हैं।❑❑

फास्ट फूड में सेहत का तड़का

वसा और मेदा हैं सबसे बड़े दुश्मन

फास्ट फूड को आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाते हैं उनमें उपयोग होने वाला तेल, और मैदा। फास्ट फूड को सेहतमंद बनाने के लिए इन दोनों सामग्रियों के इस्तेमाल पर खास नज़र रखने की ज़रूरत है। डाइटीशियंस के अनुसार 'फास्ट फूड के साथ सॉस का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। सॉस भी सेहत के लिए अच्छा नहीं। पर जो चीज सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, वह है मैदा और तेल। फास्ट फूड बनाते समय आपकी इनकी जगह अन्य सेहतमंद विकल्पों को इस्तेमाल में ला सकते हैं।

- मैदे की जगह आटे का पिज्ज बेस चुनें।
- मैदा नूडल्स की जगह सब्जियां ज़्यादा डालें। इससे टिक्की तेल कम सोखेगा।
- टिक्की को तलने के बाद उसे टिश्यू पेपर पर ज़रूर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
- पिज्जा में भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

उस पहचान से जोड़ना जिसे कांग्रेस ने बनाया और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी के अलोकतांत्रिक भारत के विरोध को मान्यता दिलाना। ज़ाहिर है इन मुद्दों के आसरे चुनाव में जीत कैसे मिलेगी या राजनीतिक विस्तार कैसे होगा ये प्रश्न पारंपरिक कांग्रेसियों के ज़हन में आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की मशक्कत राज्यवार कांग्रेस नेताओं के आसरे कांग्रेस को खड़ा करने से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को खड़ा कर राज्यों की राजनीति को साधने की है लकिन उसमें भी हर राज्य में अगुआई युवा कंधों पर हो जिसमें संघर्ष करने का माद्दा हो। मौक़ा मिलने पर उन्हें भी वैसी ही राजनीतिक ताक़त मिले जैसी प्रियंका को यूपी में मिली।

इसी कतार में संसद के भीतर भी धीरे-धीरे युवा टीम ही लोकसभा और राज्यसभा में नज़र आए। इसके लिए सड़क पर संघर्ष करते हुए मोदी के कॉपोरेट गवर्नेंस और संघ के गोडसे के हिन्दुत्व को साफगोई के साथ उठाने से कांग्रेसी चूके नहीं। पर क्या ये सब इतना आसान है। जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालेंगे नहीं, ये संभव भी कैसे होगा। 24 अकबर रोड के गलियारों में ये प्रश्न है कि जिसका जवाब भी गांधी परिवार को ही देना हे।

संकट 24 अकबर रोड पर कांग्रेसियों के कब्ज़े की लड़ाई से कहीं आगे की उस कांग्रेस का है जिसे मोदी संघ विचार से टकराते हुए कांग्रेस को ज़िन्दा रखना है। यानि सीडब्ल्यूसी की अगली बैठक पुराने तर्ज़ पर एंटोनी कमेटी बनाने की दिशा में बढ़ने के बदले 1998 के पचमढ़ी चिंतन शिविर और 2003 के शिमला चिंतन शिविर की तर्ज़ पर रास्ता खोजना चाहती है जिसमें एक समय सोनिया की एंट्री हुई और दूसरी बार कांग्रेस को भाजपा के शाइनिंग इंडिया के नारे को चुनौती देते हुए गठबंधन के आसरे 2004 में जीत मिली। 2024 का ये रास्ता सीडब्ल्यूसी के चिंतन शिविर से निकलेगा या जी-23 के संगठन में कब्ज़े से या फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने से, इस प्रश्न का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।❑❑

शेष.... बाजवा के शांति संदेश...

विदेश नीति होनी चाहिए। पाकिस्तान यदि भारत से मित्रता करता है और परस्पर लाभकारी पड़ोसी रिश्ते अपनाता है, तो वास्तव में उसकी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत के साथ सहयोग पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएगा। आर्थिक रूप से मजबूत और आंतरिक रूप से सामंजस्यपूर्ण पाकिस्तान अमेरिका,चीन, सऊदी अरब और अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकता है। जनरल बाजवा इस वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ छह माह ही बचे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं और एक सार्थक उपलब्धि हासिल कर सकते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश के शांति संदेश का सकारात्मक जवाब देना चाहिए, जो उसके सैन्य प्रमुख की ओर से आया है।❑❑

शेष.... उत्तराखंड में ....

को हम ऊंचा उठाएं। हम विकास को राजनीतिक नज़र से नहीं देखते और न ही सीटों के दायरे में इसको रखते हैं। हमारा उद्देश्य उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाना है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।

प्रश्नः- अगले वर्ष 2023 में राज्य में निकायों के चुनाव होने हैं। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। चुनाव के लिए आपके पास समय बहुत कम है ऐसे में सरकार क्या अभी से ही चुनावी मोड पर आ जाएगी?

उत्तरः- चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं और आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। सरकार का कार्य जनता के हित में कार्य कर उसके विश्वास को हासिल करना है और हमारी सरकार दिन-रात जनसेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हमें जनता का आर्शीवाद मिला है भविष्य में भी ये बरक़रार रहेगा।

प्रश्नः- आपने नारा दिया है -विकल्प रहित संकल्प। इसका आशय क्या है?

उत्तरः- इसका आशय है कि जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होना चाहिए। मतलब संकल्प को पूर्ण करना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इसी सोच को अपनाते हुए हमने यह नारा दिया है मेरी सरकार ने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है और हम इसे निश्चित ही हासिल करेंगे।❑❑

शेष.... चहल गड़े मुर्दे उखाड़ रहे...

उत्तरः- 2007 विश्व कप के फाइनल में मिस्बाह का यादगार कैच मैंने पकड़ा, जिससे भारत चैम्पियन बना। 2008 में हरभजन सिंह ने मुझे किस लिए थप्पड़ मारा। मैं अब तक नहीं जान सका हूं, लेकिन उसे भूल जाना चाहता हूं।

प्रश्नः- मलयालम में आप सात फिल्मे कर चुके हैं, बॉलीवुड से ऑफर मिलने पर करेंगे..?

उत्तरः- सही है। मलयालम में टीम-5 मेरी हिट फिल्म है। अब तेलुगु फिल्म कर रहा हूं। एक कॉमेडी फिल्म से बॉलीवुड में मेरी एंट्री होने वाली है, जिसकी शूटिंग इसी वर्ष जुलाई से होगी।❑❑

हिजाब पहनने वाली औरतों में अपनी छवि की सोच उन्नत होती है

वर्ष 2015-16 में लंदन में जांच पड़ताल शोध से यह बात सामने आयी थी कि हिजाब पहनने वाली औरतों में अपनी शारीरिक छवि की सोच अधिक बेहतर होती है और वह अपनी खूबसूरती से अधिक संतुष्ट होती हैं यह अध्ययन जर्नल बॉडी इमेज के नए अंक में प्रकाशित हुआ है जिस में विशेषज्ञों की एक टीम ने खूबसूरती के संतुष्ट धर्म और केन्द्रीय धारे में शामिल निर्वासित महिलाओं में पश्चिमी संस्कृति की क़बूलियत के बीच संबंध खंगालने की कोशिश की है। प्रोफेसर ज़ैना चीकर जो इस अध्ययन का नेतृत्व कर रही थीं और इनकी टीम ने 143 नौजवान महिलाओं को भर्ती किया जिनमें मुसलमान महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व था। इनसे इनके धार्मिक अकीदे, रूहानी तजुबात और धार्मिक कम्यूनिटी के साथ मेल जोल रखने के बारे में सवाल पूछे गए और यह सवाल किया गया कि क्या वह खुद को अपने पूर्वजों की विरासत से जुड़ा हुआ समझते हैं। शोधकर्ताओं ने अपने आंकलन में महिलाओं में पश्चिमी हुस्न की सोच का इनके मज़हबी रूझान के हवाले से निर्धारण किया। उदाहरणार्थ इस बयान के हवाले से इनकी रज़ामंदी देखी कि काश मैं इस मैग्ज़ीन की मॉडल जैसी खूबसूरत नज़र आऊं। शोधकर्ताओं को पता चला कि जो महिलाएं अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मौजूद थीं इनमें पश्चिमी खूबसूरती के स्तर के लिए दबाव कम था। इस परिणाम के विपरीत केन्द्रीय धारे में शामिल महिलाएं जिन्होने कैनेडियन संस्कृति और मूल्यों की अधिक संस्तुति की थी इनमें मीडिया की खूबसूरती के स्तर के हवाले से अधिक दबाव था जबकि धार्मिकता की उच्च सतह को खूबसूरत के इत्मीनान की सोच के साथ जोड़ा गया।

शोध विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक आसान बात है कि रूढ़िवादी पोशाक पहनने से महिलाओं में अपनी जिस्मानी छवि पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता है लेकिन यहां इस संबंध को ज़ाहिर करने में एक महत्वपूर्ण तत्व की भूमिका अदा करता है और यह मज़हबी और सांस्कृतिक परिदृश्य है जिसमें हिजाब पहना जाता हैं इस नए शोध से शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि धर्म को अकेले ही सुन्दरता के इत्मीनान के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे आइडियल खूबसूरती की सोच के विरूद्ध विरोध मिलता है। पिछले वर्ष ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक टीम ने लगभग 600 मुस्लिम औरतों का लंदन में एक इंटरव्यू किया था जिसमें 60 प्रतिशत महिलाएं हिजाब पहनती थीं। अध्ययन के परिणामों से ज़ाहिर हुआ कि जो महिलाएं विधि वत तरीक़े से नियमित हिजाब वाला लिबास पहनती थीं वह अपनी जिस्मानी छवि से संतुष्ट थीं इनमें दुबला होने की तरफ ध्यान कम था और मोटा होने का भय कम था। इन्होंने परिणाम निर्धारित किया कि पर्दा दरअसल जिस्मानी छवि के नकारात्मक सोच के ख़िलाफ़ एक ढाल बन जाता है दूसरे अध्ययनों में भी धर्म और खूबसूरती के इत्मीनान के बीच एक संबद्ध संबंध पता चला था। लेखकों का विचार है कि हिजाब पहनने और खूबसूरती की सोच के बीच जो संबंध हैं संभव है कि इसका पर्दे की सादगी से कम संबंध हो बल्कि यह बाद में और अधिक धार्मिक दृष्टिकोण इख़्तियार कर लेता है, इन औरतों के लिए जो हिजाब पहनती है मनोविज्ञान विशेषज्ञों का बहरहाल कहना है कि यकीनन धर्म जिस्मानी छवि के इत्मीनान का इलाज नहीं है लेकिन खूबसूरती से अधिक अख़्लाक़ी विश्वास और रूहानी दृष्टिकोण पर ध्यान देने से संभावित तौर पर स्तरीय अंदेशों को कम करने में मदद मिल सकती है।

शेष.... आलमे इस्लाम में ईदुल फित्र....

हैं और अपने घरों में खाने लाकर गली में सजा देते हैं और फिर सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। यूं सब अमीर व ग़रीब एक ही पंक्ति में बैठ कर खाना खाते हैं। ऐसी बराबरी और एकता की मिसाल किसी और मुश्किल है।

ट्यूनिस (ट्यूनिशिया)

ट्यूनिस में ईदुल फित्र तीन से चार दिन तक मनायी जाती है। लेकिन सरकारी स्तर पर दो ही छुटिटयों की घोषणा की जाती है। ईद की तैयारियां तो रमज़ान के आख़िरी अशरे ही में शुरू हो जाती है, इंडोनेशिया की तरह ट्यूनिस में भी मेहमानों की आवभगत के लिए बेकरियों से विशेष प्रकार के बिस्कुटस तैयार करवाए जाते हैं। यह ईद के विशेष तोहफे के तौर पर मेहमानों को पेश किए जाते हैं। इन बिस्कुटों में 'बकालवा' और काअक की कई क़िस्में शामिल है। (यह दोनों बिस्कुटस सिर्फ ईद के अवसर पर तैयार होते हैं) सुबह होते ही लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो औरतें विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्य निबटाने में लग जाती हैं, कुछ घरों की औरतें भी मर्दों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं। इसके बाद बच्चे अपने वाल्दैन के साथ दादा दादी के घर जाते हैं। घरों में तरह तरह के खाने पकते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तोहफों का आदान प्रदान किया जाता है। ट्यूनिश की परम्परा के अनुसार बच्चे अपने बाप के साथ दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो घर में औरतें मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए रूकती है, ईद के अवसर पर मिठाइयां और केक पेश करना आम है।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

बढ़ाने की सिफारिश कर चुका है, मगर इस मामले में अभी कोई उल्लेखनीय प्रगति नज़र नहीं आई है। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एम.वी. रमण भी कई अवसरों पर न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने और पदों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत रेखांकित कर चुके हैं। यहां तक कि वे सरकार से तल्ख़ लहज़े में भी इस पर ढुलमूल और पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ने को कह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अदालतों में जजों की संख्या कम होने से न्याय प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को रेखंकित किया है। तेलंगाना राज्य के न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने अपनी यह पीड़ा ज़ाहिर की। मगर सरकार इस समस्या को कब गंभीरता से लेगी, कहना मुश्किल है।

हालांकि अदालतों के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं के ज़रिए न्याय प्रक्रिया में तेज़ी लाने की भरसक कोशिश की जाती है। न्यायाधीशों के ख़ाली पड़े पद न भरे जा पाने की स्थिति में यूपीए सरकार के समय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने, अदालत का कामकाज दो पालियों में बांट कर करने का उपाय निकाला था। उसका असर भी हुआ। मगर अदालतों पर काम का बोझ इतना बढ़ चुका है कि हर न्यायाधीश अगर रोज़ सौ मामले निपटाने का प्रयास करें तो भी मुकदमों के बोझ से छुटकारा पाने में कई वर्ष लग जाएंगे। स्थिति यह है कि विचाराधीन क़ैदियों तक के मामले में सुनवाई करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस तरह कई विचाराधीन कैदी उससे अधिक सज़ा काट जाते हैं, जितनी उन्हें संबंधित अपराध में मिलती है। विचाराधीन क़ैदी के रूप में लंबे समय तक जेल में बंद रहने की वजह से कई युवाओं का भविष्य चौपट हो जाता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को अनेक मौकों पर स्वीकार कर चुका है कि विचाराधीन क़ैदियों के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मगर साक्ष्य जुटाने, जांच आदि में देर होती रहती है और फैसला लटका रहता है। इस तरह बहुत सारी जेलों में क्षमता से कई गुना अधिक क़ैदी भर गए हैं।

कहते हैं कि देर से मिलने वाला न्याय एक प्रकार से अन्याय ही होता है, क्योंकि फैसले में होने वाली देरी के चलते वादी और प्रतिवादी दोनों का काफी धन, समय और ऊर्जा बेवजह नष्ट हो चुकी होती है। आपराधिक मामलों में तो व्यक्ति को अगर बेकसूर घोषित कर भी दिया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फैसला आने से पहले तक वह समाज की नज़रों में अपराधी बनकर ही जीवन गुज़ार चुका होता है। इन तथ्यों से सरकार अंजान नहीं मानी जा सकती मगर जब भी ख़ाली पदों को भरने की बात आती है तो धन की कमी का मुद्दा उठ खड़ा हो जाता हे।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **24April 2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•सवाल सेहत का •आस्था बनाम अराजकता •मुक़दमों का बोझ

सवाल सेहत का

देश को अगले दस वर्ष में बड़ी संख्या में चिकित्सक मिलने का प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में देश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और इससे स्वास्थ्य सेवाओं की दशा-दिशा दोनों में सुधार आएगा। साथ ही सरकार ने देश के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात कही है। ये दोनों बातें कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर इन दोनों ही बिन्दुओं पर काम शुरू हो जाए तो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन आ सकता है। देश के लिए यह ऐसी ज़रूरत है कि स्वास्थ्य जैसा विषय किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज देश का स्वास्थ्य क्षेत्र अगर बीमार है, तो उसके मूल में कहीं न कहीं सरकारों की ओर से होती रही उपेक्षा भी है। वरना क्यों आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट जीडीपी का तीन प्रतिशत भी नहीं है? ज़ाहिर है, अगर देश को सेहतमंद बनाना है और नागरिकों को स्वस्थ्य रखना है तो पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारनी होगी। भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी किस बदतर हाल में है, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की किसी भी मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना हर सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकारें आज भी इस मोर्चे पर नाकाम ही नज़र आती हैं। अगर सरकारें स्वास्थ्य के मोर्चे पर सजग होती तो देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदतर न होती। अगर महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें, तो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं किस हाल सरकारी दस्तावेज़ों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र और ज़िला अस्पताल सब हैं। पर हक़ीक़त यह है कि ज़्यादा प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में डॉक्टर नहीं है, चिकित्साकर्मी नहीं है, दवाईयां और बिस्तर नहीं हैं। वरना क्यों नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में यह कहता कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि देश में आबादी की तुलना में चिकित्सकों की भारी कमी है। डेढ़ हजार लोगों पर एक चिकित्सक का होना कम गंभीर बात नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे तो कैसे स्वास्थ्य सेवाएं चलेंगी? आज भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानदंडों को हक़ीक़त में पूरा नहीं करतीं। पिछले वर्ष नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नीति आयोग को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश के ज़्यादातर अस्पताल चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। यह रिपोर्ट 28 राज्यों और 02 केन्द्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों के सर्वे के बाद तैयार की गई थीं पिछले दो सालों में कोरोना महामारी ने भी हमें बताया है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मज़बूत नहीं होगा तो हम कैसे संकटों में फंस सकते हैं। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और बढ़ेगी ही। ऐसे में अगर सरकारें अब भी नहीं चेती तो इसकी कीमत बीमार नागरिकों के रूप में देश को चुकानी पड़ेगी।

आस्था बनाम अराजकता

आमतौर पर यही माना जाता है कि पर्व-त्यौहार या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन समाज में सौहार्द की भावना को मज़बूत करने के अवसर होते हैं। ऐसे आयोजनों में शामिल लोग आपसी कड़वाहटों को भी भूल कर इंसानियत के रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। यों भी हर धर्म का मूल तत्व मानवीय मूल्यों का प्रसार करना है और यह सुनिश्चित करना हर धार्मिक आस्था से जुड़े व्यक्ति की ज़िम्मेदारी भी है लेकिन पिछले कुछ समय से धर्म और आस्था से जुड़े कार्यक्रमों की प्रकृति में जिस तरह से बदलाव देखें जा रहे हैं, वे बेहद चिंताजनक और दुखद है। हालत यह है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली भी ऐसे विवादों और हिंसा से मुक्त नहीं रह पा रही है। इस वर्ष रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान जैसे दृश्य में देखने में आए और उसके बाद जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुईं, उनसे ज़ाहिर है कि सद्भाव के मौके अब अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच तनाव और टकराव तक में बदल रहे हैं। प्रश्न है कि दुनिया में किस धर्म के मूल्य इंसानियत के विरुद्ध प्रतिद्वंद्विता और हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं।

गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप करके हालात को संभालने की कोशिश लेकिन लेकिन इस बीच सामने आई घटनाओं ने किसी भी संवेदनशील और ज़िम्मेदार नागरिक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आस्था और पर्व के आयोजन में नाहक प्रतिद्वंद्विता के लिए कितनी जगह होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो अन्य पक्षों को ऐसे कितने संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। विडंबना यह है कि जहांगीरपुरी में जो हुआ, उसमें अमूमन सभी पक्षों ने ग़ैरजिम्मेदारी, लापरवाही और उतावलेपन का प्रदर्शन किया। नतीजतन, जुलूस पर पथराव और फिर हिंसा की घटनाओं ने आस्था प्रदर्शन के एक मौके को दुखद स्वरूप दे दिया। प्रश्न है कि हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के आयोजकों को यह ध्यान में रखने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि अगर यात्रा में शामिल लोग हथियार प्रदर्शन या किसी स्तर पर कानून की कसौटियों का उल्लंघन कर रहे हैं और उससे उकसावे या उत्तेजना जैसी स्थिति बन रही है तो उसे संभाला जाए। फिर दूसरे पक्ष को अगर जुलूस की कोई गतिविधि आपत्तिजनक लगी, तो उस पर खुद कोई अराजक प्रतिक्रिया करने के बजय उन्होंने पुलिस की मदद लेने ज़रूरत क्यों नहीं समझी।

इसके अलावा शोभायात्रा में शामिल लोगों की गतिविधियां आदि देखने के बावजूद पुलिस ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? अब पुलिस की ओर से कहा गया कि उस जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हैरानी की बात है कि किसी छोटी घटना पर भी तत्काल प्रतिक्रिया की हालात संभालने की क्षमता रखने का दावा करने वाली पुलिस की इजाज़त के बिना सरेआम ऐसी शोभायात्रा का आयोजन कैसे संभव हो पाया? अगर ऐसा था तो पुलिस ने हिंसक माहौल पैदा होने के पहले उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जब देश में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाके के रूप में दिल्ली में अराजकता और हिंसा का माहौल बनाने में कुछ लोगों को कामयाबी मिल जाती है तो इसके कैसे देखा जाना चाहिए? यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिल्ली अभी दो वर्ष पहले हुए दंगों का दर्द भूल भी नहीं पाई थी। धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता इस देश की असली ताक़त और पहचान रही है। इसे नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की कोशिश सफल, दंगों में फंसाए गए 9 युवाओं को अदालत ने किया बरी

हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है : मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली : दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के तीन मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। एक मामले में नवागंतुकों के मामले से धारा 436 को हटा दिया गया है क्योंकि यह धारा उन पर लागू नहीं होती। अदालत ने इस मामले को निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया है, दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी जावेद को बच्चों के लिए दाख़िले के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी है, जबकि तीसरे मामले आरोपी आरिफ को उसकी दादी की मौत की वजह से 25 दिन की अंतरिम ज़मानत दी गई है। बता दें कि ये तमाम मामले जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर जमीयत द्वारा लड़े जा रहे हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के कानूनी विशेषज्ञ एडवाकेट नियाज़ फारूकी ने कहा कि हमें अदालतों से न्याय की काफी उम्मीदें हैं। मुकदमों की पैरवी कर रहे एडवोकेट सलीम ने कहा, 'हम अब तक ज़्यादातर मामलों में सफल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सभी दोष मुक्त हो जाएंगे। कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के तीन अलग-अलग मामलों में अंतरिम ज़मानत देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। मौलाना महमूद मदनी ने तीनों मामलों में अंतरिम ज़मानत और बरी होने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और हम मामले को पूरी ताक़त से लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बेगुनाह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे और सभी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के कानूनी विशेषज्ञ मौलाना नियाज़ अहमद फारूक़ी साहब ने कहा कि हम शुरू से ही इन मामलों को लड़ रहे है, हम सफल अवश्य होंगे।

मुक़दमों का बोझ

भारतीय अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के चलते मुकदमों के लंबे समय तक खिंचते जाने और मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ते जाने की शिकायत पुरानी है। कई प्रधान न्यायाधीश अपनी पीड़ा ज़ाहिर कर चुके हैं। एक प्रधान न्यायाधीश की आंखों से तो सेवानिवृत्ति के अवसर पर बोलते हुए इस विषय को लेकर आंसू तक निकल पड़े थे। हर विधि आयोग न्यायालयों की क्षमता

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173